प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 29 – 06 मई 2019 मूल्य पांच रूपए

# बिन्दल को हुए नोटिस से जयराम सरकार आयी सवालों में

**शिमला/शैल।** जयराम सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल के खिलाफ डेढ़ दशक से चल रहे आपराधिक एवम् भ्रष्टाचार मामले को पिछले वर्ष उस समय वापिस ले लिया था जब यह मामला एक तरह से फैसले के कगार पर पंहुच चुका था। क्योंकि इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सारी गवाहीयां हो चुकी थी। केवल इसमें नामज़द अभियुक्तों के ही धारा 313 के तहत ब्यान होने बाकी थे। इन ब्यानों के बाद बहस और फिर फैसले की स्टेज ही शेष बची थी। ऐसे में इस स्टेज पर आकर विजिलैन्स द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 में आवेदन दायर करके मामलों को वापिस लेना सरकार और जांच ऐजैन्सी की नीयत तथा नीति पर गंभीर सवाल उठाता है। फिर जब आपराधिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय यह व्यवस्था दे चुका हो कि Every acquittal has to be viewed seriously शीर्ष अदालत की इस व्यवस्था के बाद हिमाचल उच्च न्यायालय भी जुलाई 2016 में कैप्टन राम सिंह के मामले में निचली अदालत द्वारा वहां आये धारा 321 के आवदेन को स्वीकार करने के फैसले को पलट चुका है।

यही नहीं 13 सितम्बर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस चन्द्र चूढ़ पर आधारित पीठ का एक फैसला आ गया था। इसमें धारा 321 पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अदालत ने यह कहा कि We are compelled to recapitulate that there are frivolous litigations but that does not mean that there are no innocent sufferers who eagerly wait for justice to be done. That apart, certain criminal offences destroy the social fabric. Every citizen gets involved in a way to respond to it; and that is why the power is conferred on the Public Prosecutor and the real duty is cast on him/her. He/ she has to act with responsibility. He/she is not to be totally guided by the instructions of the Government but is required to assist the Court; and the Court is duty bound to see the precedents and pass appropriate orders.

In the case at hand, as the aforestated exercise has not been done, we are compelled to set aside the order passed by the High Court and that of the learned Chief Judicial Magistrate and remit the matter to the file of the Chief Judicial Magistrate to reconsider the application in accordance with law and we so direct.

The appeal is, accordingly, allowed.

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के परिदृश्य में यह और फिर भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जयराम सरकार ने इस मामले को वापिस क्यों लिया। गृह और विजिलैन्स विभाग मुख्यमन्त्री जयराम के अपने पास हैं। फिर जयराम से लेकर मोदी तक भाजपा का सारा शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता के दावे करता है।

अब इस मामले को पवन ठाकुर ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर बिन्दल समेत सभी अभियुक्तों और सरकार को नोटिस जारी कर दिये हैं वैसे तो आपराधिक मामलों में इस तरह की याचिका डालना केवल पीड़ित पक्ष का ही अधिकार होता है। इस मामले में प्रत्यक्षत: पीड़ित पक्ष सरकार ही है और उसकी ओर से कोई अपील दायर नही हुई है। ऐसे में तीसरे व्यक्ति की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना सर्वोच्च न्यायालय की समय समय पर आयी व्यवस्थाओं का ही परिणाम माना जा रहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले में अन्तिम फैसला क्या आता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इस मामले से जयराम सरकार की विश्वसनीयता के साथ ही विपक्ष की भूमिका भी सवालों में आ जाती

है क्योंकि चुनावों के बीच आये उच्च न्यायालय के नोटिस पर विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही आयी है। याद रहे कि 1999 में राजीव बिंदल सोलन नगर समिति के अध्यक्ष थे तो उस समय परिषद में हुई नियुक्तियों में उन्होंने कानूनों का उल्लंघन कर डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोगों को भर्ती कर दिया था।

1999 में प्रदेश में भाजपा-हिविंका गठबंधन की सरकार थी। बाद में 2000 में बिंदल सोलन हलके के हुए उप चुनाव में विधायक बन गए थे। इसके बाद 2003 में सता में आई वीरभद्र सिंह सरकार ने इन नियुक्तियों की जांच कराई व विजीलैंस ने 2006 में बिंदल व बाकियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 और 120 बी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2)के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन तब अदालत में चालान पेश नहीं हो पाया। दिसंबर 2007 में प्रदेश में दोबारा से धूमल सरकार सत्ता में आ गई और यह मामला लटक गया। बाद में दिसंबर 2012 में सत्ता में आई वीरभद्र सिंह सरकार में जुलाई 2013 में बिदंल व बाकियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर सरकार ने अभियोजन को मंजूरी दे दी। बिंदल के अलावा इस मामले में नगर समिति सोलन के तत्कालीन पार्षद हेमराज गोयल, डीके ठाकुर और समिति के कार्यकारी अधिकारी एससी कलसोत्रा मुख्य रूप से आरोपी बनाए गए थे। बाकी आरोपी जिन्हें नियुक्त किया गया था, वह थे।

वीरभद्र सिंह सरकार में ट्रायल शुरू हुआ। प्रदेश में जब जयराम सरकार सत्ता में आई तो इस मामले की पैरवी कर रहे वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी व पूर्व निदेशक अभियोजन सतीश ठाकुर को जयराम सरकार ने नहीं हटाया। सतीश ठाकुर ने ही जांच अधिकारी समेत मुख्य गवाहों की गावाहियां जयराम सरकार में ही करवाई। सरकार के एक साल सत्ता में आ जाने के बाद सतीश ठाकुर को हटाया गया।

लेकिन तब केवल सीआरपीसी की धारा 313 के तहत ब्यान होने ही बाकी बचे थे। इस बीच जयराम सरकार की ओर से अदालत में बिंदल के खिलाफ मामले को वापस लेने के लिए अर्जी दायर की गई लेकिन अदालत ने कहा कि केवल एक आरोपी के खिलाफ मामला वापस नहीं हो सकता।

ऐसे में सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामले वापिस लेने की अर्जी दायर की व सेशन जज सोलन ने भूपेश शर्मा ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर ली। पवन ठाकुर की ओर से पैरवी कर रही वकील सुनीता शर्मा ने कहा कि चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए गए हैं।

इस मामले के दोबारा उठने से बिंदल का मंत्री बनना मुश्किल में आ सकता है। बिंदल एक अरसे से जयराम सरकार में मंत्री पद हासिल करने की जुगत में है लेकिन वह अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं।

# 2017 की शिकायत पर अब जांच के आदेश

**शिमला/शैल।** राज्य सूचना आयोग ने 11 अप्रैल को पारित अपने एक आदेश मे प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को न्यूरोसर्जन डा. जनक के खिलाफ 2017 में आयी एक शिकायत पर वांच्छित कारवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये हैं। इस कथित शिकायत पर क्या कारवाई हुई है इस बारे में आरटीआई एक्टिविस्ट डा. बन्टा ने स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह जानकारी न दिये जाने पर यह मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंच गया था जहां पर यह आदेश हुए हैं।

After hearing both the parties in detail and perusing the case file, the Commission observes that the PIO has denied the information with regard to RTI application dated 08-08-2018 by invoking the provisions of section 11(1) of the RTI Act. In this regard, the commission feels that the PIO has not followed the prescribed time schedule as provided in the Act with regard to dealing 3rd party information as provided in the Act. Further, considering the submissions made by both the parties, the Commission is of the view that as the enquiry has not been culminated, the provisions of section 8(1) (h) would be applicable in this case and according , it is ordered that as and when the same is accomplished, the PIO still provide complete in formation to the appellant, strictly as per his RTI application, free of cost. Further, the Commission also feels that as considerable time has elapsed to take action on the complaint made during September 2017, the matter is brought to the notice of Principal Secy., Health Govt. of H.P Shimla for appropriate action. With these observations and directions, these two second appeals are disposed off by a single order. Inform the parties accordingly.

इन आदेशों में यह सामने आया है कि यह कथित शिकायत सितम्बर 2017 में वन मन्त्री ठाकुर सिंह भरमौरी और तत्कालीन मुख्यमन्त्री द्वारा की गयी थी। 2017 में प्रदेश विधानसभा के लिये चुनाव हुए थे जिनमे भरमौरी हार गये थे और सत्ता भाजपा के हाथ आ गयी थी। लेकिन जब सितम्बर 2017 में यह शिकायत हुई थी तब उस समय तो कोई चुनाव आचार सहिंता लागू नही थी फिर इस शिकायत के बाद करीब चार माह तक यह सरकार सत्ता में रही थी। ऐसे मे जब शिकायत करने वाला स्वयं मन्त्री और मुख्यमन्त्री रहा हो तो उस समय इस पर जांच क्यों नही हो पायी। क्या अधिकारियों की नजर में यह शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और इसी कारण से इस पर कोई कारवाई की आवश्यकता नही समझी गयी। लेकिन अब जिस ढंग से आरटीआई के माध्यम से इस शिकायत को अब स्वास्थ्य सचिव तक ला दिया गया है उससे कुछ अलग ही संकेत उभर रहे हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य सचिव पर नजरें आ गयी है। क्योंकि सूचना आयोग के निर्देशों के बाद इसमें कुछ तो कारवाई करनी ही पड़ेगी।

# झूठ और फरेब की राजनीति कर रही कांग्रेसःसहजल

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और विनाश के नाम पर चुनाव लड़ रही है। सहजल कसौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास और विनाश की इस जंग में भाजपा की जीत होगी क्योंकि विकास का दूसरा रूप विकास है। उन्होंने कहा कि चुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस का विनाश होना तय है।

राजीव सहजल ने कहा कि कांग्रेस के नेता धर्म और जाति पर आधारित राजनीति कर जनता को गुमराह कर उन्हें बांटने का प्रयास कर रहे हैं तभी वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जाति पूछ रहे हैं। सहजल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुसूचित जातियों के लिए 95 हजार करोड़ रूपये सभी अधिक की राशि खर्च की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा सरकार ने पूरे देश में हर वर्ग का एक समान विकास करवाया है।

सहजल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इसके नेता शुरू से ही गरीबी हटाओ का नारा लगाते आए हैं और आज भी गरीब हटाओ का ही नारा दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को पहुंचा है और आज हर गरीब आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है। सहजल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी आए दिन झूठ बोलते रहते हैं और जब झूठ का पर्दाफाश होता है तो फिर माफी मांगते फिरते रहते है। उन्होंने कहा कि इससे सपष्ट झलकता है कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। सहजल ने अपने विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को भारी बहुमत से जिताने की बात भी कही।

# संजय कुंडू की कुवैत के राजदूत के साथ ग्लोबल इंवेस्टर मीट पर चर्चा

**शिमला/शैल।** प्रधान आवासीय आयुक्त संजय कुंडू ने नई दिल्ली में कुवैत के राजदूत जसीम प् अल-नजीम के साथ मुलाकात की तथा उन्होंने 26 व 27 सितम्बर, 2019 को धर्मशाला में प्रस्तावित 'ग्लोबल इंवेस्टर मीट' से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने राजदूत को इस प्रस्तावित 'इंवेस्टर मीट' के बारे में अवगत करवाया तथा उन्हें अपने देश के व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल के साथ इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने दूतावास से कुवैत की प्रमुख निजी और सार्वजनिक कम्पनियां से हिमाचल में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने को कहा।

प्रधान आवासीय आयुक्त ने उन्हें सूचित किया कि राज्य सरकार प्रदेश में अधोसंरचना के विस्तार तथा बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल एंड वेलनेस केन्द्र, शहरी विकास तथा आवास, आईटी, इलैक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल आदि क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। प्रदेश सरकार कुवैत को इन क्षेत्रों में निवेश के लिए एक अग्रणी भागीदार के रूप में देख रही है।

राजदूत ने कहा कि कुवैत भी हिमाचल प्रदेश के साथ साझेदारी के लिए तत्पर है तथा इस प्रदेश में बुनियादी ढांचे और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का इच्छुक है। उन्होंने शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की इच्छा व्यक्त की।

# पंजाब विश्वविद्यालय नें हिमाचल के मुख्य सचिव को नवाजा एम.फिल की डिग्री से

**सोलन/शैल।** हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में आयोजित दीक्षांत समारोह में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा एम.फिल की डिग्री से नवाजा गया।

बी.के.अग्रवाल ने आई.आई.टी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में स्नात्कोतर डिग्री प्राप्त की है। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ''कन्कलुसीव लैंड टाईटल सिस्टम फॉर इंडिया'' पर किए गए शोध के आधार पर एमफिल की यह डिग्री प्रदान की गई है।

यह डिग्री सैंट्ल कमांड के जीओसी लैंफ्टिनैंट जनरल अभय कृष्णा द्वारा प्रदान की गई। इस अवसर पर कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल टीएन चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और पूर्व रक्षा सचिव योगेन्द्र नारायण भी उपस्थित थे।

# एंटी हेल नेट पर सब्सिडी 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़:आरडी धीमान

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाले सेब की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा शिमला के कुफरी में दूसरे एप्पल कनक्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार में होर्टिकल्चर विभाग के एडिशन चीफ सेक्रेटरी आरडी धीमान बतौर मुख्यातिथि तथा होर्टिकल्चर विभाग के निदेशक डा. एमएल धीमान बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए।

हिमाचल प्रदेश सरकार में होर्टिकल्चर विभाग के एडिशन चीफ सेक्रेटरी आरडी धीमान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब की फसल को ओलों से बचाने के लिए एंटी हेल नेट पर सब्सिडी 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी है जो बहुत बड़ी बढ़त है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न बागवानी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम विभिन्न चरणों में है और इसका लाभ निकट भविष्य में उत्पादकों को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार एक उच्च स्तरीय समिति भी बना रही है जिसमें फल उत्पादक, सरकार, अनुसंधान संस्थान और उद्योग को शामिल किया जाएगा। यह कमेटी राज्य में बागवानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-मंथन और और उनके निवारण का मंच साबित होगी।

इस अवसर पर सीआईआई हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन हरीश अग्रवाल ने कहा कि सीआईआई का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरने की क्षमता है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश एप्पल कॉन्क्लेव को राज्य के सेब उत्पादकों को कुशल, सशक्त और मजबूत बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सभा को कई प्रसिद्ध फसल देखभाल समाधान प्रदाताओं जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, एलायंस एग्री टेक, कॉर्टेवा एग्रीसाइंस आदि के विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने संबोधित किया। इसके साथ ही डा. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ होर्टिकल्चर एंड फॉरेस्टरी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भी सेब उत्पादकों को संबोधित किया। किसानों से प्रगतिशील उत्पादकों की सफल कहानियों को साझा किया गया और यह भी बताया गया कि यह उन्होंने कौन सी बैस्ट प्रैक्टिस अपनाकर किया है।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन कर्नल शैलेष पाठक ने अपने संबोधन में सेब उत्पादकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य के सेब उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की सुविधा सीआईआई देगा और उनके मुद्दों को उपयुक्त स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। एप्पल कॉन्क्लेव में उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण, स्प्रे शेडयूल, मृदा स्वास्थ्य, पौधे पोषण प्रबंधन, नवीन फसल देखभाल समाधान, बेहतर फसल के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारी के खतरों आदि विभिन्न मुद्दों और उनके पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य भर से करीब 275 सेब उत्पादकों ने इस कनक्लेव में हिस्सा लिया।

# मोदी सरकार की योजनाएं से धरातल पर लोग हुये लाभान्वितःसुरेश कश्यप

**शिमला/शैल।** शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुख्यधारा के अर्थतंत्र से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जो-जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई है उनसे धरातल स्तर पर लोग लाभान्वित हुये हैं। कश्यप ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के देवठी, चामत बडेच, देलगी, भारती, हरिपुर, खलबा, पट्टा बरौरी, जाबल जमरोट, जाडली, गम्बरपुल, कक्ड़ हट्टी व सुबाथू में जनसम्पर्क अभियान के तहत चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में 1 करोड़ 53 लाख से अधिक घरों का निर्माण, 10 करोड़ परिवारों का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 14 करोड़ 64 लाख लोगों का दुर्घटना बीम, 5 करोड़ 67 लाख परिवारों का जीवन बीमा, 9 करोड़ 74 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण और समुचे देश में अन्न सुरक्षा का लाभ देकर सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचाकर विचैलियों की दलाली से मुक्ती मिली है।

सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रकृति के विभिन्न रंगों को बिखेरता कसौली उत्तर भारत के प्रतिष्ठित व पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। रोजाना हजारों पर्यटकों की आवाजाही वाले कसौली में वैसे तो पूरा साल ही पर्यटकों भी भीड़ जमा रहा करती है, पर गर्मियों के मौसम में यहां के मुख्य दार्शनिक स्थलों जैसे क्राइस्ट चर्च, अप्पर माल, लोअर माल, मंकी प्वाइंट, सन राइज प्वाइंट, सन सेट प्वाइंट हेरिटेज मार्केट व सीआरआई का ऐतिहासिक भवन आदि में पर्यटकों को पैर रखने की जगह तक नही मिलती है। उन्होंने कहा कि इस पर्यटन स्थल को और सुदृढ बनाने के लिए पर्यटकों के लिए सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि कसौली में पर्यटकों की सहुलियत के लिए रज्जूमार्ग बनाने की संभावनाओं को भी तलाशा जायेगा। कश्यप ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रमुखता दी जा रही है।

# 100 मिनट में करना होगा शिकायत का निपटारा

**शिमला/शैल।** लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी यदि कोई शिकायत हो तो उसे सी- विजिल नामक एप के जरिए भी भेजा जा सकता है। यह सुविधा कोई भी व्यक्ति अपने एंडरॉयड फोन पर सी-विजिल ऐप डाउनलोड करके हासिल कर सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने बताया कि सी- विजिल एप के जरिए भेजी गई शिकायत का निपटारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक 100 मिनट के भीतर किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति फोटो या ऑडियो-वीडियो के रूप में अपनी शिकायत इस माध्यम से दर्ज करवा सकता है। शिकायत अपलोड हो जाने के बाद शिकायत की जांच की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को बाकायदा एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा जिससे वह शिकायत पर की गई कार्रवाई को भी जान सकेगा।

उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के पास जाती है। जीपीएस सिस्टम की मदद से शिकायत वाली जगह की पहचान की जाती है और इसके तुरंत बाद इसे जांच के लिए फील्ड इकाई को दे दिया जाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि पहले से ली गई फोटो या रिकॉर्ड किए वीडियो को अपलोड करने की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप की यह विशेषता है कि यह सिर्फ चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर ही कार्य करेगी।

उपायुक्त ने कहा कि सी विजील एप के अलावा उपायुक्त कार्यालय में भी एक टोल फ्री नंबर 1800-180-2875 और लैंडलाईन नंबर 01792-223696 स्थापित किया गया है। इन नंबरों के अलावा टोल फ्री नंबर 1950 (वोटर हेल्प लाईन) पर भी मतदान अथवा मतदाता संबंधी जानकारी हासिल की जा सकती है।

# प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाये 22425 मामलें

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के पास 30 अप्रैल, 2019 तक कुल 33128 मूल आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 22425 मामलों का अन्तिम निपटारा किया जा चुका है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 839 अवमानना याचिकाएं, 36 समीक्षा याचिकाएं, 123 निष्पादन याचिकाएं और 9148 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि ट्रिब्यूनल के पास हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से 6485 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 1694 मामलों का निपटारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल, 2017 तथा 14 अप्रैल, 2018 को दो सदस्यों के (प्रशासन) कार्यकाल पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में वर्तमान में अध्यक्ष बैंच और एक न्यायिक सदस्य बैंच कार्य कर रहा है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

# शिमला में युवती के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग का हिमाचल सरकार को नोटिस

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य मीड़िया सचिव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष की जनसभाओं और बैठके पर सरकारी खुफिया विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार नजर गडाये है और उनकी पूरी जानकारी हर शाम भाजपा को दे रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए क्या क्या रणनीति बना रही है जो लोकतंत्रीय प्रणाली में जयराम सरकार की गलत और ओछी हरकत है।

राज्य मीडिया सचिव ने बताया कि 5 अप्रैल 2019 को भी जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठियोग के अपने चुनावी दौरे पर थे तो राज्य खुफिया एजेंसी सीआईडी का एक व्यक्ति आल्टो कार मे लगातार वहां पहुंच रहा था जहां जहां प्रदेशाध्यक्ष सभाएं कर रहे थे। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता को उक्त व्यक्ति की गतिविधियों पर शक हुआ तब उससे पूछताछ की वो संतोषजनक जबाब नही दे पाया।

उक्त व्यक्ति अपनी कार में लगातार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पिछा कर रहा था जानकार सुत्रों से पता चला कि यह व्यक्ति खुफिया विभाग का है। बलदेव ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार सता प्राप्ती के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग छोडे और असली जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव लडे क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और तो और हरियाणा राज्य महिला आयोग ने प्रदेश सरकार को पिछले दिनों शिमला के अन्दर युवती के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर नोटिस भेजकर जवाब तलबी की है जो हिमाचल के लिये निदंनीय है। बलदेव ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मामले की हाईकोर्ट के जज या सीबीआई से जांच की मांग कर चुकी है किन्तु भाजपा के मुख्यमंत्री और अन्य नेता चुनाव रैलियों मे व्यस्त हैं जिनको हिमाचल की बहु बेटियों की कोई चिन्ता नही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निन्दा करती है।

# हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले मंदिर जाकर माँग रहे आशीर्वाद:गोविन्द ठाकुर

**शिमला/शैल।** भारतीय जनता पार्टी के नेता व हिमाचल प्रदेश सरकार में वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने मंडी से जारी विज्ञप्ति में कहा कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास का नया अध्याय लिख रहा है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी

बदली आबो हवा में अवसरवादिता का अभूतपूर्व अध्याय लिखने में व्यस्त है। कुछ समय पूर्व बहुसंख्यकों को कोसने वाले अब खुद के हिंदू होने पर गर्व का दावा कर रहे हैं। चुनावों के दौरान नास्तिक भी अपनी आस्तीन पर अपना धर्म – जाति ओढ़कर चलते हैं। कांग्रेस ने अचानक फैसला किया कि वह अपने अध्यक्ष राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण करार देगी। उन्हें अब शिव भक्त घोषित कर दिया गया है। वह मंदिरों में जाने का मौका नहीं गंवाते और ऐसे अवसरों को बड़े कार्यक्रम के तौर पर पेश करते हैं, मगर देश ने उनका 2004, 2009 या 2014 में धार्मिक रुझान कभी नहीं देखा।

उन्होंने कहा कि कल तक भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले और राम सेतु को तोड़ने का प्लान बनाने वाले अब ''राम पथ'' बनवाने की बात कर रहे हैं। हाल में ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। वे जिस लिपुलेख दर्रे के रास्ते यात्रा पर गए उधर से कम से कम 21 दिन लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने 9 दिनों में ही यात्रा पूरी कर ली। मीडिया के सवालों पर वो अपनी यात्रा के बारे में चुप्पी साध लेते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जिसके नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राममंदिर निर्माण की सुनवाई रोकने का हलफनामा देते हैं अब वही कांग्रेस राममंदिर बनवाने की बात करती है। गोबिन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि दशकों से हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कांग्रेसी नेता अब मंदिर – मंदिर जाकर सत्ता का आशीर्वाद माँग रहे हैं। खद्ध को जनेऊ धारी और शिवभक्त बताने वाले राहुल गांधी हिंदू संस्कृति पर लांछन लगाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। जिन लोगों ने 70 सालों तक माँ गंगा के लिए कुछ नहीं किया उन्हें विरूपित होने दिया आज वो गंगा जल का आचमन कर रहे हैं। हिंदू आतंकवाद, हिंदू पाकिस्तान हिंदू तालिबान की थ्यौरी देने वाली कांग्रेस ने अब हिंदूओं की हिमायती होने का चोला धारण कर लिया है। जगह और जरूरत के हिसाब से चोले बदलने वाली कांग्रेस पार्टी का हिसाब जनता इन चुनावों में करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सबका साथ सबका विकास नीति अपनाई और किसी का तुष्टिकरण नहीं बल्कि सबका सशक्तिकरण के अपने एजेंडे के साथ देश की राजनीति को नई दिशा दी, कांग्रेस की ये अवसरवादिता उसी का परिणाम है।

# भाजपा शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था राम भरोसे

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने शिमला में 19 वर्षीय छात्रा के साथ हुये बलात्कार की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुये प्रदेश के लिए इसे शर्मनाक घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि चोरी और डकैती प्रदेश में आम बात हो गई हैं तथा शिमला में 19 वर्षीय छात्रा के साथ हुये बलात्कार की घटना से महिलाओं की सुरक्षा की पोल खुल गई है।

अनुराग शर्मा ने भाजपा नेताओं को याद दिलाया कि गुड़िया प्रकरण पर दिनरात राजनीति करने वाले भाजपा नेता आज इस युवति को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं प्रर्दशन कर रहे। प्रदेश सरकार अपनी बदनामी को छुपाने के लिए प्रभावित छात्रा के उपर दबाव बनाकर अपने ब्यान बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रा द्वारा पुलिस से सहायता मांगने पर भी उसकी शिकायत को जिन अधिकारियो व कर्मचारियों ने गम्भीरता से नहीं लिया उनके विरुद्ध अभी तक प्रदेश सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। अनुराग शर्मा ने कहा कि हि. प्र. कांग्रेस सेवादल इस घटना की उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत न्यायधीश से जांच की मांग करता है। प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है उस समय से प्रदेश की राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था राम भरोसे है। आये दिन प्रदेश में अपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता सत्ता के मोह में इतने डूब चुके हैं कि आम जनता से भाजपा का कोई सरोकार नहीं रहा है।

अनुराग शर्मा ने आरोप लगाया कि गत वर्ष प्रदेश सरकार की लाचार कार्यप्रणाली की वजह से विश्वविख्यात पर्यटन स्थल शिमला की जल संकट के चलते पुरी दुनिया में बदनामी हुई। प्रदेश सरकार तथा भाजपा शासित नगर निगम पानी की व्यवस्था करने की बजाये समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से पेयजल अभाव के कारण पर्यटको को शिमला न आने की अपील करते रहे जिससे शिमला मे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगो को भरी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और देश व विदेश से शिमला आने वाले पर्यटकों के मन में शिमला के प्रति आकर्षण कम हुआ। समय रहते यदि प्रदेश सरकार तथा नगर निगम पेय जल व्यवस्था के उचित प्रबन्ध करती तो शिमला का नाम बदनाम नहीं होता।

प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि लोक सभा चुनावों से पहले सीमेंट तथा रसोई गैस की कीमतो में वृद्धि कर मोदी सरकार ने प्रदेश की जनता को एक और तोहफा दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा आम जनता के प्रति कितनी गम्भीर है। सीमेंट के दाम बढ़ा कर केन्द्र सरकार ने कम्पनियों को करोड़ों का लाभ पंहुचाया है ताकि ये सीमेंट कम्पनियां चुनाव में परोक्ष तौर पर भाजपा की आर्थिक मदद करे।

कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष ने कहा कि लोक सभा चुनाव में दोबारा सत्ता हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। चुनाव में अपनी पराजय देख कर भाजपा नेता बौखलाहट में आकर अनाप शनाप ब्यानबाजी कर रहे हैं। अनुराग शर्मा ने कहा कि चारों लोकसभा सीटों पर हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने का मन बना लिया है। प्रदेश की जनता नरेन्द्र मोदी तथा प्रदेश में भाजपा सरकार की जुमले बाजी से तंग आ चुकी है। घोषणाओं एवं जुमलेबाजी के सिवा धरातल पर भाजपा सरकार ने कोई कार्य नहीं किये है।

# दूषित पानी से उत्पन्न होने वाले रोगों को लेकर रहें सावधान:विनोद कुमार

**शिमला/शैल।** उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने जिले में जल जनित रोगों से बचाव के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सतकर्तता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि जल जनित रोग गंभीर रूप धारण कर लें उससे पहले ही समय रहते इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि खुले में बेचे जा रहे शीतल पेयजल, कटे व अत्यधिक पके फलों समेत अन्य खाद्य पदार्थो के बिक्री स्थलों पर सम्बन्धित अधिकारी औचक निरीक्षण की कार्यवाही अमल में लायें ताकि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो।

उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बेचे जा रहे शीतल पेयजल व खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता व स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित बनाये कि जिले के होटलों, ढाबों व रेस्तरांओ में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ न केवल ढके हुए हों बल्कि उनमें गुणवत्ता व स्वच्छता भी रहनी चाहिए।

उन्होंनें निर्देश देते हुए कहा कि गली – सड़ी सब्जियों व फलों की बिक्री पर अंकुश लगाने की दिशा में भी विभागीय अधिकारी कड़ी कार्यवाही अमल में लायें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व बन जाता है कि वे ''जल जनित रोगों'' के बचाव के लिए व्यापक पग उठाएं। उन्होंने कहा कि जिले के जिले के सभी पेयजल जल भण्डार टैंकों और प्राकृतिक जल स्त्रोंतों की सफाई के अलावा उनमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाने की दिशा में निरंतर सक्रियता से कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है।

उपायुक्त ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे जलजनित रोगों की गंभीरता को समझते हुए इस सीजन के दौरान पूरी एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि दूषित जल के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाले रोगजनक सूक्ष्म जीव पनपते हैं। लोग केवल उन्हीं प्राकृतिक जल स्त्रोतों व बावड़ियों का ही जल प्रयोग में लाएं जो सुरक्षित हों। उन्होंने बताया कि जिला में पेयजल की स्वच्छता व गुणवत्ता के लिए नियमित रूप से टेस्टिंग व निरिक्षण की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा अमल मे लाई जाए।

# शराब के जब्त स्टॉक को चोरी करने के मामले में एफआईआर दर्ज

**सोलन/शैल।** आबकारी विभाग ने सोलन जिले में कुनिहार – शिमला सड़क मार्ग पर लूनपुल यूनिट के तहत स्थित शराब की दुकान को बिना विभाग की अनुमति के जाबल जमरोट में स्थानांतरित करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शराब और बीयर की 520 बोतलों के स्टॉक को जब्त कर दिया था। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन ने बताया कि जब्त किए गए स्टॉक का अनुमानित मूल्य 1,17,333 रुपये आंका गया था।

उन्होंने बताया कि जब्त किए गए स्टॉक को लेकर आगामी कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्ट को आयुक्त आबकारी दक्षिण क्षेत्र शिमला को भेज दिया गया था। इस बीच 25 अप्रैल को अर्की सर्कल के आबकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के मुताबिक जिस शैड में जब्त किए गए स्टॉक को रखवा गया था उसे टूटा हुआ पाया गया। विभाग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना धर्मपुर में 26 अप्रैल को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भी दर्ज करवा दी गई थी। विभाग ने इसके तुरंत बाद की गई जांच में ये भी पाया कि लूनपुल यूनिट की एक अन्य शराब की दुकान में 140.989 बल्क लीटर शराब और बीयर का स्टॉक ज्यादा पाया गया जिसमें लाइसेंस धारक द्वारा ही चोरी करने का संदेह प्रतीत हुआ। विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 43 के उल्लंघन को लेकर भी अलग से मामला दर्ज कर दिया गया है।

# बायोमीट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न वितरण न करने पर वसूला जुर्माना

**हमीरपुर/शैल।** जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मिलाप शांडिल ने बताया कि जिला के विभिन्न विकास खण्डों में कार्यरत 12 उचित मूल्य की दूकानों को मार्च, 2019 के लिए बायोमिट्रिक प्रणाली से खाद्यान्नों के वितरण में लापरवाही बरतने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। अप्रैल, 2019 में भी उनकी बायोमिट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की प्रतिशतात में खास सुधार नहीं देखा गया जिस कारण उनके द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इन डिपू धारकों से 33,332 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त दो थोक व्यापारियों को भी निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के लिए 24332 रुपये जुर्माना किया गया।

जिला नियन्त्रक ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपनी उचित मूल्य की दुकानों में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को भेजकर बायोमिट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न प्राप्त करें ताकि खाद्यान्नों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सभी उपभोक्ता खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु महीने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें।

उन्होनें उपभोक्ताओं से आवाहन किया कि जिस भी उपभोक्ता ने राशन कार्ड बनवाया है वे उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न अवश्य लें क्योंकि राशनकार्डो के हिसाब से ही उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न भेजें जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता दो महीने से अधिक तक खाद्यान्न नहीं लेता है तो इसका यह मतलब निकलता है कि उसे खाद्यान्नों की आवश्यकता नहीं है और उसका आवंटन रद्द भी किया जा सकता है।

**एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए।** "आचार्य चाणक्य"

## सम्पादकीय

# लोकतन्त्र पर उठते सवाल

लोकसभा चुनावों के चार चरण पूरे हो गये हैं और इनमें 373 सीटों पर मतदान हो चुका है। 272 सीटों पर मतदान होना शेष है। 373 सीटों पर हुए मतदान में किस पार्टी को क्या मिला होगा इसका पता तो परिणाम आने पर ही लगेगा। लेकिन अब तक हुए मतदान से जो महत्वपूर्ण बिन्दु उभर कर सामने आये हैं उसमें एक है कि देश की व्यापारिक राजधानी मुबंई में 50% से कम मतदान हुआ है। दूसरा बिन्दु है कि इस मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल में ममता बैनर्जी को सीधे धमकी दी है कि उनकी पार्टी के चालीस विधायक उनके संपर्क में हैं और अब उनकी खैर नही है। ममता को धमकी देने के बाद दिल्ली से भी खबर आ गयी कि वहां भी केजरीवाल की सरकार तोड़ने के लिये भारी निवेश किया जा रहा है। वहां शायद एक विधायक भाजपा में चला भी गया है। इन धमकीयों के बाद वाराणसी में सपा के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द किये जाने का मामला भी सामने आ गया है। तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द होना कानून के जानकारों के मुताबिक एकदम कानून विरोधी है। इस नामांकन को रद्द करने के लिये जिस तरह से सारा कुछ घटा है उससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक गहरा आघात लगा है। यह नामांकन रद्द होने पर जिस तरह का रोष सामने आया है उसका वीडियो कुछ घन्टो में ही 25 लाख लोगों ने शेयर कर डाला है। हर आदमी ने इस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल उठने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर नाराज़गी जताई तब जाकर आयोग ने आचार संहिता के खुले उल्लंघन के मामलों का संज्ञान लेना शुरू किया और कुछ नेताओं के चुनाव प्रचार पर कुछ कुछ समय के लिये प्रतिबन्ध भी लगाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमितशाह के मामलों में आयी शिकायतों पर जब आयोग ने कुछ नहीं किया तब सर्वोच्च न्यायालय को इस पर भी निर्देश देने पड़े कि आयोग छ: मई तक इसपर फैसला ले। इस पर आयोग कितनी कारवाई करता है और कितनी क्लीन चिट देता है और इस सब पर शीर्ष अदालत कैसे क्या संज्ञान लेती है इसका पता आगे चलेगा। ईवीएम वोटिंग मशीनों की मतदान के दौरान खराबी की कई शिकायतें आ गयी हैं। इन शिकायतों के बाद इक्कीस राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय से फिर गुहार लगायी है कि वीवीपैट के मिलान की संख्या बढ़ाई जाये। इस पर आयोग को नोटिस भी हो गया है। वीवीपैट की शिकायत की प्रक्रिया पर एतराज उठाते हुए एक और याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो चुकी है। इस पर भी आयोग से जवाब मांगा गया है।

इस तरह यह जितनी भी घटनायें घटी हैं यह सब अपने स्वस्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रधानमन्त्री मोदी देश का सबसे बड़ा सम्मानित पद है जिस पर लोकतन्त्र की रक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी आती है। इस समय चुनाव चल रहे हैं। इसका परिणाम देश का भविष्य तय करेगा। इसके लिये देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर खुले मंच से निष्पक्ष सार्वजनिक बहस होनी चाहिये थी लेकिन देश के बुनियादी सवालों पर यह बहस कहीं दूर दूर तक देखने को नही मिल रही है। पूरा चुनाव प्रचार सोशल मीडिया और टीवी चैनलों तक ही सीमित हो कर रह गया है। यह आरोप लग रहे हैं कि न्यूज़ चैनलों के एंकरो ने पार्टीयों के स्टार प्रचारकों की जगह ले ली है। प्रधानमन्त्री स्वयं जब चुनाव प्रचार के दौरान एक राज्य की चयनित सरकार को तोड़ने की अपरोक्ष में धमकी देंगे तो क्या उसे लोकतन्त्र के प्रति उनकी आस्था माना जायेगा या हताशा। बीएसएफ का एक बर्खास्त जवान जब देश के प्रधानमन्त्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाये तो क्या इसे देश में सही और स्वस्थ लोकतन्त्र होने की संज्ञा नही दी जा सकती थी? इस जवान के युवा लड़के की हत्या हुई है और उसके हत्यारे अभी तक पकड़े नही गये हैं क्या इसके लिये मोदी और उनके मुख्यमन्त्री योगी को उन हत्यारों को शीघ्र पकड़ने के निर्देश नहीं देने चाहिये थे? तेज बहादूर यादव ने खराब खाना जवानों को खिलाने की शिकायत की थी और जब उसकी शिकायत पर कोई कारवाई नही हुई तब उसने उस खाने का वीडियो जारी कर दिया। क्या खराब खाने की शिकायत करना कोई अपराध है बल्कि इस शिकायत के लिये उसके साहस की प्रशंसा की जानी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसे सज़ा देकर निकाल दिया गया। इस बर्खास्तगी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में उसकी याचिका लंबित है। जब तेज बहादूर यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और नामांकन दायर कर दिया तब यदि प्रधानमन्त्री ने उसके साहस की सराहना की होती और पीड़ा संज्ञी की होती तो उससे प्रधानमन्त्री का ही कद बढ़ता। वह महामानव हो जाते लेकिन यहां तो यह नामांकन रद्द करवाने का आरोप अपरोक्ष में उन पर ही आ गया है। इसमें प्रधानमन्त्री का सीधा दखल था या नहीं यह नहीं कहा जा सकता लेकिन यह तो स्वभाविक है कि उनके चुनाव क्षेत्र में और कौन–कौन उनके खिलाफ चुनाव में है इसकी जानकारी उन्हें होगी ही। फिर जब इतना बड़ा यह मुद्दा बन गया तब भी प्रधानमंत्री की इस पर कोई प्रतिक्रिया न आना अपने में कई सवाल खड़े कर जाता है। यही स्थिति प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने और हार्दिक पटेल को यह अनुमति न मिलने पर है। आज राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मुद्दा जिसे सर्वोच्च न्यायालय 2015 में समाप्त कर चुका है उसे गृह मन्त्रालय के माध्यम से फिर उठाये जाने से प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर रहा है। आज इन सारे मुद्दों को जिस तरह से उछाला गया है उससे भविष्य में लोकतन्त्र की स्थिति क्या होगी उसको लेकर सवाल उठने स्वभाविक है। क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म, हिंसा और अपराध का पाठ नही पढ़ाता है। अपराध और हिंसा कोई भी धर्म और जाति से नही जुड़ते है बल्कि यह व्यक्ति का अपना स्वभाव और उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। जन्म से सभी एक समान ही होते है। ऐसे में हिंसा को धर्म से जोड़ने का प्रयास अपरोक्ष में लोकतन्त्र को कमजोर करने का प्रयास है।

# लोकसभा सांसदों के नाम खुला पत्र

**–कुलदीप शर्मा–**

आदरणीय महानुभाव

पाएं लागूं

कुशलता के समानान्तर ढेर सारे खतरों के बीच बैठा मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ और आपकी कुशलता की प्रभु से कामना कर रहा हूँ. आप मुझे नहीं जानते फिर भी मैं यह जानता हूँ कि आजकल आपको मेरी तलाश है बल्कि मुझे लग रहा है आप मेरे बारे में चिंतित भी हैं, बकौल दीवार फिल्म का अमिताभ 'आप मुझे ढूँढ रहे हैं और मैं यहाँ हूँ बिल्कुल आपके आसपास' आपका कृपाकटाक्ष पाने के लिए बेचैन हर बार मुझे लगता है मेरे दिन फिरने वाले हैं। हर बार मैं ठगा जाता हूँ, मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरे ठगे जाने का आपके मन में कोई मलाल ही नहीं है।

मेरी पहचान और मेरी औकात इतनी भर है कि मैं वोटर हूँ, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का वोटर, मुझे आप हिकारत और शरारत से एक दिन का राजा कहते हैं। जितनी चिंता आपको मेरी है आजकल मुझे सचमुच राजा जैसी बेचौनी हो रही है, यह भी नहीं जानता कि वोटर होना मेरे लिए वरदान या है या अभिशाप, मैं बड़ी उम्मीदों और उत्साह से वोट डालने जाता हूँ पर ज्योंही मैं अपना वोट डालता हूँ त्योंही अपनी लोकतान्त्रिक शक्तियों से च्युत हो जाता हूँ और फिर पांच साल बाद आने वाले उस दिन का इंतजार करने बैठ जाता हूँ जब मुझे फिर से राजा बनाया या समझा जाएगा। पिछले 60 सालों का अनुभव है कि यह पांच साल बड़े पीड़ादायक होते हैं। अपनी जीत की खुशी में जब आप जलूस निकाल रहे होते हैं हारों से लदे फदे, चेहरे पर प्लास्टिक मुस्कान चिपकाए, हवा में ही हाथ जोड़े उस अनाम भीड़ का अभिवादन, धन्यवाद कर रहे होते हैं तब मैं कहाँ होता हूँ यह सोचने या जानने की आपको फुर्सत नहीं होती। आप जब कोई मंत्री पद या निगम का अध्यक्ष पद हथियाने के लिए राजनेतिक गोटियाँ भिड़ा रहे होते हैं उस समय मैं अकेला नीम अँधेरे में आपके चुनावी घोषणा पत्र को उन्नीसवीं बार पढने की कोशिश कर रहा होता हूँ।

मान्यवर! मैं वोटर हूँ जानता हूँ कि यही मेरी नियति है मुझे आपसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद पालनी ही नहीं चाहिए। ले देकर एक वोट ही है न मेरे पास, वो पहले ही आपके नाम हो चुका है, अब मेरे पास बचा ही क्या है। आप अपने आलीशान सरकारी बंगले या लक्जरी फ्लैट में आराम से पसरे मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे ऐसी कल्पना भर मेरे लिए बहुत सुखदायक होती है, परन्तु आप क्या सोचते हैं क्या करते हैं यह जान पाने का कोई माध्यम नहीं है मेरे पास। आपकी भी अपनी मजबूरीयां हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने सपने हैं, अपनी महत्वकांक्षाएँ हैं, उसमे मैं कहाँ आता हूँ, फिर भी मैं हर बार आपका बहुमूल्य ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की धृष्टता करता हूँ। मैंने आपको भाग्यविधाता बना कर राजधानी भेज दिया अब मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अपने वादों और आश्वासनों का पुलिंदा जो आपने मुझे दिया है वह मेरी घोर हताशा के अँधेरे में एकमात्र उजाले की किरण है। मैं आपके दिए इस पुलिंदे को बहुत सहेज कर रखता हूँ, गरीब बच्चे के खिलोने की तरह।

इस बार भी आप मुझे अच्छे अच्छे जादुई खिलौनों से बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस बार भी नई नीतियों नई योजनाओं नये संकल्पों नये वादों का मरहम लेकर आये हैं– पर क्या करूं मेरे जख्मों कि टीस कम नहीं होती। इस बार भी आप गरीबी, महंगाई, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के प्रति इतने चिंतित दिख रहे हैं कि मन यकीन करने का हो रहा है लग रहा है कि यह सब बुराइयाँ बीमारियाँ गयीं कि गयीं। सभी राजनीतिक दलों में गरीब मजलूम के लिए चिंतित दिखने की अद्भुत होड़ है। चोर सिपाही में प्रेममयी गठजोड़ है। लगता है लोकतंत्र अपने परम पवित्र रूप में इस पावन धरा पर अवतरित हो रहा है। मैं तो पूरी तरह चमत्कृत हूँ। पहले मैं सडक किनारे ताजा फूलों के हार लिए आपके लिए खड़ा रहता था और आप लालबत्ती की खतरे वाली गाडी में एक अजीब भयानक सी आवाज करते हुए मेरे सामने से सीधे विश्राम गृह की ओर निकल जाते थे जहाँ खाकी वर्दी पहने कुछ लोग ठक ठक बंदूकें उठाकर आपको सलाम करते थे। मेरे दिल की दुआ और हाथों के फूल मायूसी में मुरझा जाते थे। कितने अचम्भे की बात है कि आज आप स्वयं पैदल चल कर मेरे पास आ रहे हैं। मैं तो कृतज्ञ हो गया। जनाब आप इतना कष्ट न उठाएं, आपका शरीर और आपके पांव इसके अभ्यस्त नहीं हैं। (पांच साल आपके पांवों में रहता हूँ इसलिए जानता हूँ) आप केवल इतना बता दें कि जो कुछ आप मंचों से भाषणों में या चुनावी घोषणा पत्रों में कह रहे हैं– वह सच है? क्या सचमुच इस बार आप इतने अच्छे काम करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मैं भुजा उठाकर कहता हूँ कि मेरा वोट क्या मेरा तन मन भी आप पर फिदा होगा, और अगर जीवन में कभी मेरे पास धन आया तो वह भी आप पर ही न्योछावर होगा। आफ्टर आल आपकी तरह मैं भी देशभक्त हूँ जी।

आपने कल अपने भाषण में भ्रष्टाचार की खिलाफत की सो बहुत ही अच्छा किया। आप ऐसा करते रहेंगे तो भ्रष्टाचारियों को भी सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलेगा। समाज में समानता के नये अध्याय का सूत्रपात होगा जी। बापू का सपना पूरा होगा दरअसल भ्रष्टाचार के विषय में आप जब भी मुंह खोलते हैं शोर करते हैं, तमतमाते हैं तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह अलग बात है कि कुछ सिरफिरे आप को ही भ्रष्टाचारी कहने लगते हैं, पर मैं आपकी बात मानता हूँ, कोई अपने भाषण में इतना झूठ थोड़े ही बोल सकता है! जो लोग झूठ बोलते हैं जी आप ऐसे लोगों को जरुर सबक सिखाना जी।

बुरा न माने तो एक बात कहूँ पता नहीं मुझे क्यूँ लगता है कि आप जनता रूपी विक्रमादित्य के बैताल हैं। जब जब विक्रमादित्य मुंह खोलेगा आप गायब हो जाएंगे, पर विक्रमादित्य फिर पांच साल के लिए आपको कंधे पर लाद लेगा और आप उसे फिर कोई मनघडन्त कहानी सुनाएंगे वह फिर मुंह खोलेगा और आप फिर गायब। यह अनोखा खेल चलता ही रहेगा। आप ही बताएं मान्यवर! इस खेल में कौन क्या मजा आ रहा है? आमजन तो ठगा ही जा रहा है न, जिसकी आपको इतनी चिंता है उसे बार बार जख्म देना और फिर दहाड़ मार कर हँसना आपको अच्छा लगता है क्या? आप बहुत समझदार हैं जी, आपको क्या बताना। आप वहां संसद में बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं जो मुझे समझ नहीं आतीं। मुझे लगता है कि अभी आप मेरा जिक्र भी करेंगे पर ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी आप सो भी जाते हैं जी वहां. टी वी दिखाता है।

इस बार आप राम भगवान के मन्दिर का भी जिक्र कर रहे हैं अपने भाषणों में, अच्छा है जी मन्दिर बना दो, कहीं भी बना दो जी, हम मत्था टेक लेंगे जी। भगवन तो भगवन हैं पर हमारे भगवान तो आप ही हैं जी। आप हमारे बेटे को नौकरी जरुर पर जरुर दिला देना, बडा उदास रहता है। बाकि आप सब जाणी जान है। गैस वालों को भी बोलना सिलिंडर के पैसे थोड़े घट लिया करें। पुगाणा मुश्किल हो गया है जी। वोट तो मैं आप को डाल दूंगा जी पक्का।

# मोक्ष नगरी में मोदी का मायावी संसार

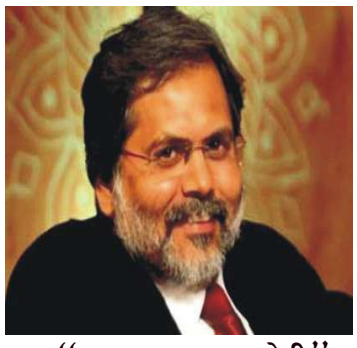

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर यह बनारस है। तो क्या बनारस पहली बार उस राजीनिति को नया जीवन देगा जिस पर से लोकतंत्र के सरमायेदारों का भी भरोसा डिगने लगा है। फिर बनारस तो मुक्तिद्वार है। और संयोग देखिये वक्त ने किस तरह पलटा खाया जो बनारस 2014 में हाई प्रोफाइल संघर्ष वाली लोकसभा सीट थी, 2019 में वही सीट सबसे फिकी लडाई के तौर पर उभर आई। जी, देश के सबसे बडे ब्रांड अंबेसडर के सामने एक ऐसा शख्स खडा हो गया जिसकी पहचान रोटी – दाल से जुडी है। यानी चाहे अनचाहे नरेन्द्र मोदी का ग्लैमर ही काफूर हो गया जो सामने तेज बहादुर खडा हो गया। राजनीतिक तौर पर इससे बडी हार कोई होती नहीं है कि राजा को चुनौती देने के लिये राजा बनने के लिये वजीर या विरोधी नेता चुनौती ना दे बल्कि जनता से निकला कोई शख्स आ खडा हो जाये, और कहे मुझे राजा नहीं बनना है सिर्फ जनता के हक की लडाई लडनी है। तो फिर राजा अपने और को कैसे दिखाये और किसे दिखाये। क्योंकि राजा की नीतियों से हारा हुआ शख्स ही राजा को चुनौती देने खड़ा हुआ है तो फिर राजा के चुनावी जीत के लिये प्रचार की हर हरकत अपनी जनता को हराने वाली होगी। जो जनता की नहीं राजा की हार होगी। और ये सच राजा समझ गया तो व्यवस्था ही ऐसी कर दी गई कि जनता से निकला शख्स सामने खडा ही ना हो पाये। तो सूखी रोटी और पानी वाले दाल की लडाई करने वाले तेजबहादुर का पर्चा ही उस चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया जो खुद राजा के रहनुमा पर जी रहा है। तो क्या ये मान लिया जाये कि ये बनारस की ही महिमा है जिसने मुक्ति द्वार खोल दिया है और मोक्ष के संदेश देने लगा है। क्योंकि बनारस को पुराणादि ग्रंथो के आसरे परखियेगा तो पुराणकार बताते हैं कि काशी तीनों लोकों में पवित्रतम स्थान रखती है, ये आकाश में स्थित है तछा मर्त्यलोक से बाहर है....

**वाराणसी महापुण्या त्रिशुलोकेशु विश्रुता। अन्तरिक्षे पुरी सा तु मर्त्यलोक बाह्यात।।**

**हे पार्वती ! तीनो लोकों का सार मेरी काशी सदा धन्य है।**

**वाराणसीति भुवनत्रयसारभूता धन्या सदा ममपुरी गिरिराजपुत्री।**

लेकिन बनारस तो सियासी छल कपट, धोखा फरेब की सियासत में इस तरह जा उलझी है। जहां राजा एक राज्य संभालते हुये चुनावी दस्तावेज में खुद को अविवाहित बताता है। लेकिन देश संभालने के वक्त खुद को विवाहित बताता है। शिक्षा प्राप्त करते हुये मिलने वाली डिग्री भी चुनाव दर चुनाव बदलती है लेकिन राजा तो राजा है इसलिये वसंतसेना भी जब पांच बरस में ग्रेजुएट से बारहवीं पास हो जाती है तो भी चुनाव आयोग को कुछ गलत नहीं लगता। और तो और देश भर में चुनाव लडने वालों में 378 उम्मीदवार अपराधी या भ्रष्टाचार के दायरे में है, लेकिन लोकतंत्र ऐसी खुली छूट देता है कि चुनाव आयोग उन्हे छू भी नहीं पाता। लेकिन जनता से निकला तेजबहादुर जब राजा की नीतियों पर रोटी का सवाल उठाकर शिंकजा कसता है तो पहले नौकरी से बर्खास्तगी फिर लोकतंत्र की परिभाषा तले चुनाव लड़ने पर ही रोक लगाने में समूचा अमला लग जाता है। जिससे राजा को कोई परेशानी ना हो कि आखिर वह जनता को क्या कहेगा... जनता को हरा दो। मुश्किल है तो फिर राजा काशी की महत्ता उसके सच को क्या जाने। वह तो आस्था को चुनावी भावनाओं की थाली में समेट पी लेना चाहता है। तभी तो काशी की पहचान को ही बदल दिया जाता है। ऐसे में काशी की वरुणा और अस्सी नदी तो दूर गंगा तक ठगा जा रहा है तो फिर अतीत की काशी को कौन परखे कैसे परखे। एक वक्त माना तो ये गया कि वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित बनारस में स्नान, जप, होम, मरण और देवपूजा सभी अक्षय होते हैं। लेकिन गंगा का नाम लेकर सियासत इन्हे भूल गई और गंगा की पहचान बनारस में है क्या इस समझ को भी सत्ता सियासत समझ नहीं पायी। बनारस में गंगा का पानी भक्त कभी घर नहीं ले जाते। क्योंकि बनारस में तो गंगा भी मुक्तिद्वार है। काशी के प्रति लोगो में आस्था इस हद तक बढी कि लोग विधानपूर्वक आग में जलकर और गंगा में कूदकर प्राण देने लगे, जिससे कि मृतात्मा सीधे शिव के मुख में प्रवेश कर सके। उन्नीसवीं सदी तक लोग मोक्ष पाने के विचार से, यहां गंगा में गले में पत्थर बांधकर डूब जाते थे। आज भी इस विचार को समेटे लोग बनारस पहुंचने वाले कम नहीं है। लेकिन अब तो इक्कीसवी सदी है और गंगा मुक्ति नहीं माया का मार्ग है। इसीलिये तो बनारस की सडकों पर मुक्ति नहीं सत्ता का द्वार खोजने के लिये जब तीन लाख से ज्यादा लोगों को नरेन्द्र मोदी के प्रचार के लिये लाया गया और गंगा को समझे बगैर, बनारस की महत्ता जाने बगैर अगर मेहनताना लेकर सभी राजा के लिये नारा लगाते हुये आये और खामोशी से लौट गये तो फिर चाहे अनचाहे भगवान बुद्ध याद आ ही जायेगें। भगवान बुद्ध भी अपने धर्म का प्रथम उपदेश देने सबसे पहले बनारस ही आये थे। उन्होने कहा था.....

**भेदी नादयितुं धर्म्या काशी गच्छामि साम्प्रतम।**
**न सुखाय न यशसे आर्तत्रणाय केवलम्।।**

यानी धर्मभेरी बजाने के लिये इस समय मैं काशी जा रहा हूं – न सुख के लिये और न यश के लिये, अपितु केवल आर्तो की रक्षा के लिये।

तो हालात कैसे बिखरे हैं, संस्कृति कैसे बिखरी है इसलिये बनारस की पहचान अब खबरों के माध्यम से जब परोसी जाती है तो चुनावी बिसात पर है और धर्म सबसे बड़ी राजनीति। संघ परिवार धर्म की नगरी से दिल्ली की बनारस की तहजीब, बनारस का संगीत, बनारस का जायका या फिर बनारस की मस्ती को खोजने में लगते हैं। और काशी की तुलना में दिल्ली को ज्यादा पावन बताने में कोई कोताही भी नहीं बरतता है।

लेकिन 2019 में नरेन्द्र मोदी और तेज बहादुर का सियासी अखाड़ा बनारस बना तो फिर बनारस या तो बदल रहा है या फिर बनारस एक नये इतिहास को लिखने के लिये राजनीतिक पन्नों को खंगाल रहा है। बनारस से महज कोस पर सारनाथ में जब गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला पाठ पढ़ा, तब दुनिया में किसी को भरोसा नहीं था गौतम बुद्ध की सीख सियासतों को नतमस्तक होना भी सिखायेगी और आधुनिक दौर में दलित समाज सियासी ककहरा भी बौद्ध धर्म के जरीये ही पढेगा या पढ़ाने की मशक्कत करेगा। गौतम बुद्ध ने राजपाट छोडा था। मायावती ने राजपाट के लिये बुद्ध को अपनाया। इसी रास्ते को रामराज ने उदितराज बनकर बताना चाहा और समाजवादी पार्टी ने तो गौतम बुद्ध की थ्योरी को सम्राट अशोक की तलवार पर रख दिया। सम्राट अशोक ने बुद्धम शरणम गच्छामी करते हुये तलवार रखी और अखिलेश यादव ने तेजबहादुर के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने के बाद समझा कि समाजवादी बनाकर संघर्ष करवा दिया जाये तो सियासत साधी जा सकती है। तो अखिलेश ने सत्ता गच्छामी करते हुये सियासी तलवार भांजनी शुरु की। पर बनारस तो मुक्ति पर्व को जीता रहा है फिर यहां से सत्ता संघर्ष की नयी आहट नरेन्द्र मोदी ने क्यों दी। मोक्ष के संदर्भ में काशी का ऐसा महात्म्य है कि प्रयागगादु अन्य तीर्थो में मरने से अलोक्य, सारुप्य तथा सानिध्य मुक्ती ही मिलती है और माना जाता है कि सायुज्य मुक्ति केवल काशी में ही मिल सकती है। तो क्या सोमनाथ से विश्वनाथ के दरवाजे पर दस्तक देने नरेन्द्र मोदी 204 में इसलिये पहुंचे कि विहिप के अयोध्या के बाद मथुरा, काशी के नारे को बदला जा सके। या फिर संघ परिवार रामजन्मभूमि को लेकर राजनीतिक तौर पर जितना भटका, उसे नये तरीके से परिभाषित करने के लिये मोदी को काशी चुनना पड़ा। लेकिन 2019 में जिस तरह काशी को मोदी ने सियासी तौर पर आत्मसात कर लिया है उसमें मोदी कहीं भटके नहीं है। क्योंकि काशी को तो हिन्दुओं का काबा माना गया। याद कीजिये गालिब ने भी बनारस को लेकर लिखा, 'तआलल्ला बनारस चश्मे बद्दूर, बहिस्ते खुर्रमो फिरदौसे मामूर, इबादत खानए नाकूसिया अस्त, हमाना काबए हिन्दोस्तां अस्त।'

यानी हे परमात्मा, बनारस को बुरी दृष्टि से दूर रखना, क्योंकि यह आनंदमय स्वर्ग है। यह घंटा बजाने वालों अर्थात हिन्दुओं का पूजा स्थान है, यानी यहीं हिन्दुस्तान का काबा है। तो फिर तेज बहादुर यहां क्यों पहुंचे। क्या तेज बहादुर काशी की उस सत्ता को चुनौती देने पहुंचे हैं, जिसके आसरे धर्म की इस नगरी को बीजेपी अपना मान चुकी है। या फिर तेजबहादुर के अक्स तले अखिलेश यादव को लगने लगा है कि राजनीति सबसे बड़ा धर्म सत्ता पर अपने राजनीतिक स्वयंसेवक को देख रहा है। और अखिलेश यादव, तेजबहादुर यादव के जरीये काशी में नैतिक जीत से दिल्ली की त्रासदी से मुक्ति चाहने लगे। तो क्या सब प्रचीन नगरी कासी को ही सियासत पंचतंत्र की कहानियों में तब्दिल करना चाहती है जिससे यहां की सांस्कृतिक महत्ता खत्म हो जाये। क्योंकि बनारस की राजनीतिक बिसात का सच भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि जितनी तादाद यहां ब्राह्मण की है, उतने ही मुसलमान भी है। करीब ढ़ाई – ढ़ाई लाख की तादाद दोनों की है। पटेल डेढ़ लाख तो यादव एक लाख है और जायसवाल करीब सवा लाख। मारवाडियों की तादाद भी 40 हजार है। इसके अलावा मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, सिख और राजस्थानियों को मिला दिया जाये तो इनकी तादाद भी डेढ लाख से उपर की है। तो 17 लाख वोटरों वाले काशी में मोदी का शंखनाद गालिब की तर्ज पर हिन्दुओं का काबा बताकर मोदी का राजतिलक एक बार फिर कर देगा या फिर काशी को चुनौती देने वाले कबीर से लेकर भारतेन्दु की तर्ज पर तेजबहादुर की चुनौती स्वीकार करेगा। क्योंकि गालिब बनारस को लेकर एकमात्र सत्य नहीं है। इस मिथकीय नगर की धार्मिक और आध्यात्मिक सत्ता को चुनौतियां भी मिलती रही है। ऐसी पहली चुनौती 15 वीं सदी में कबीर से मिली। काशी की मोक्षदा भूमि को उन्होंने अपने अनुभूत – सच से चुनौती दी और ऐसी बातों को अस्वीकार किया। उन्होंने बिल्कुल सहज और सरल ढंग से परंपरा से चले आते मिथकीय विचारों को सामने रखा और बताया कि कैसे ये सच नहीं है। अपने अनुभव ज्ञान से उन्होने धार्मिक मान्यताओं के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, जो एक ओर काशी की महिमा को चुनौती देता था तो दूसरी ओर ईश्वर की सत्ता को। उन्होंने दो टूक कहा – जो काशी तन तजै कबीरा। तो रामहिं कौन निहोरा। यह ऐसी नजर थी, जो किसी बात को, धर्म को भी, सुनी – सुनायी बातों से नहीं मानती थी। उसे पहले अपने अनुभव से जांचती थी और फिर उस पर भरोसा करती थी।

काशी का यह जुलाहा कबीर कागद की लेखी को नहीं मानता था, चाहे वह पुराण हो या कोई और धर्मग्रंथ। उसे विश्वास सिर्फ अपनी आंखो पर था। इसलिये कि आंखों से देखी बातें उलझाती नहीं थी.....तू कहता कागद की लेखी, मै कहता आंखन की देकी। मै कहता सुरझावनहरी, तू देता उरझाई रे। वैसे बनारस की महिमा को चुनौती तो भारतेन्दु ने 19 वीं सदी में भी यह कहकर दी.....देखी तुमरी कासी लोगों, देखी तुमरी कासी। जहां बिराजे विस्वनाथ, विश्वेश्वर जी अविनासी। ध्यान दें तो बनारस जिस तरह 2014 का सियासी अखाडा बन रहा था 2019 के हालात ठीक उसके उलट है। 2014 में नेताओ के कद टकरा रहे थे। 2019 में जनता के कद के आगे राजा का बौनापन है जो बनारस को जीता है और जीत भी सकता है। यानी 2014 में सियासी आंकड़े में कूदने वाले राजनीति के महारथियों को जैसे जैसे बनारस के रंग में रंगने की सियासत भी शुरु हुई है। वह ना तो बनारस की संस्कृति है और ना ही बनारसी ठग का मिजाज। लेकिन अब तो वाकई काशी की जमीन पर गंवई अंदाज में काशी मे मुक्ति का सवाल है। और मुक्ति जीत पर भारी है। इसे दिल्ली का राजा चाहे ना समझे लेकिन काशी वासी समझ चुके है। पर उनकी समझ को भी राजा अपने छाती पर तमगे में टांगना चाहता है। पर राजा ये नहीं जानता कि काशी को जीत कर वह हार रहा है क्योंकि राजा का लक्ष्य तो अमेरिका है। और बनारस को बिसमिल्ला खां के दिल को जीता है।

बिस्मिल्ला खां ने अमेरिका तक में बनारस से जुड़े उस जीवन को मान्यता दी, जहां मुक्ति के लिये मुक्ति से आगे बनारस की आबो हवा में नहाया समाज है। शहनाई सुनने के बाद आत्ममुग्ध अमेरिका ने जब बिस्मिल्ला खां को अमेरिका में हर सुविधा के साथ बसने का आग्रह किया तो बिस्मिल्ला खां ने बेहद मासूमियत से पूछा, सारी सुविधा तो ठीक है लेकिन गंगा कहां से लाओगे। और बनारस का सच देखिये। गंगा का पानी हर कोई पूजा के लिये घर ले जाता है लेकिन बनारस ही वह जगह है जहा से गंगा का पानी भरकर घर लाया नहीं जाता। तो ऐसी नगरी में मोदी किसे बांटेंगे या किसे जोड़ेंगे। वैसे भी घंटा – घडियाल, शंख, शहनाई और डमरु की धुन पर मंत्रोच्चार से जागने वाला बनारस आसानी से सियासी गोटियों तले बेसुध होने वाला शहर भी नहीं है। बेहद मिजाजी शहर में गंगा भी चन्द्राकार बहती है बनारस हिन्दु विश्वविघालय के 35 हजार छात्र हो या काशी विद्यापीठ और हरिश्चन्द्र महाविद्यालय के दस – दस हजार छात्र। कोई भी बनारस के मिजाज से इतर सोचता नहीं और छात्र राजनीति को साधने के लिये भी बनारस की रंगत को आजमाने से कतराता नहीं। फिर बनारस आदिकाल से शिक्षा का केन्द्र रहा है और अपनी इस विरासत को अब भी संजोये हुये हैं। ऐसे में सेना के जवान हाथों में सूखी रोटियां और पानी की दाल का सच दिखाकर पहचान पाये हैं तो दूसरी तरफ गुजरात के राजधर्म और दिल्ली के लोकतंत्र पर चढाई कर नरेन्द्र मोदी बनारस में है। मोदी की बिसात पर बनारसी मिजाज प्यादा हो नहीं सकता और तेज बहादुर सियासी बिसात पर चाहे प्यादा साबित हो खारिज कर दिये गये लेकिन बनारसी मिजाज तो उन्हे मोक्ष दे रहा है। क्योंकि मोदी वजीर बनने के लिये लालालियत हैं और तेज बहादुर मुक्ति पाने की छटपटाहट में बनारस पहुंचे हैं। तो फिर बनारस का रास्ता जायेगा किधर। नजरें सभी की इसी पर हैं। क्योंकि बनारस की बनावट भी अद्भुत है। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है। आधा शंख में है और काशी का आखरी सच यही है कि यहां सूई की नोंक भर भी स्थान नहीं है, जहां जाने वाले को मोक्ष ना मिले। और मोक्ष में लिंग, जाति, वर्ण, वर्ग का कोई भेद नहीं होता। तो आप तय किजिये मोक्ष किसे मिलेगा या किसे मिलना चाहिये।

# साध्वी प्रज्ञा:हिन्दू आतंकवाद,सत्य या मिथक?

**गौतम चौधरी**

आखिरकार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 'शहीद हेमंत करकरे के सर्वनाश' होने का कथित श्राप वाले बयान को दिनभर मचे हंगामे के बाद अपना बयान वापस ले लिया और भाजपा ने उसे उनका निजी बयान मानकर अपना पल्ला झार लिया है। साध्वी इस बयान के बाद ज्यादा ही चर्चा में आ गयी हैं। साध्वी, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहीं हैं। इस राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से हेमंत करकरे, मालेगांव, समझौता, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, मोडासा ब्लास्ट के आरोपियों और हिंदू आतंकवाद का मामला सामने आ गया है।

दरअसल, साध्वी प्रज्ञा की शहीद हेमंत करकरे पर बयानबाजी के बीच जो सवाल सामने आए हैं उनमें सबसे अहम यह है कि क्या मुंबई आतंकी हमले के दौरान अगर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अजमल कसाब और अबु इस्माइल की गोली का शिकार करकरे नहीं होते तो इस साध्वी के ग्रुप के निशाने पर होते और तब भाजपा की सरकार उनके उपर जांच बिठाती?

कायदे से देखें तो साध्वी उक्त विस्फोटों के मामलों में दोषी भी हैं और बेकसूर भी हैं। साध्वी पर अपने सहयोगी सुनिल जोशी की हत्या के भी आरोप हैं। कोई आरोपी कसूरवार और बेकसूर दोनों नहीं हो सकता है लेकिन मालेगांव बम कांड 2008 की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोषी भी हैं और बेकसूर भी। जब दिल्ली और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी, तब वह दोषी थीं। अब दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तब वह बेकसूर हो गयी हैं। मतलब यहां कसूरवार या बेकसूर होने का फैसला अदालत से नहीं, राजनीतिक दलों के हिसाब से हो रहे हैं। अब यहां एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जब पहले वाले कथित इस्लामिक आरोपी बेकसूर हो गए और दूसरे वाले कथित हिन्दू आतंकवादियों को भी एक-एक कर दोषमुक्त कर दिया गया तो आखिर बम फोड़ा किसने? यह प्रश्न विकट है और इस प्रश्न का जवाब देश की सरकार को देना होगा नहीं तो जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे और उसका लाभ स्वभाविक रूप से देश को अस्थिर करने वाली ताकत को मिलेगा।

संभवत: ऐसी विचित्र मिसाल भारत जैसे देश में ही देखने को मिल सकती है, जहां किसी केस में कोई दोषी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस आरोपी की वफादारी किस राजनीतिक दल के साथ है। बहरहाल, जैसा कि सब जानते हैं, न्यायिक हिरासत में करीब आठ साल से जेल में रहीं साध्वी प्रज्ञा को राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो (एनआईए) की ओर से 13 मई 2016 को दायर पूरक आरोपपत्र में क्लीनचिट दे दी गयी। उसके बाद ही कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही साध्वी को जमानत मिल गई है। साध्वी को क्लीनचिट देने का अर्थ है कि बमकांड में उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, जिसके आधार पर वह दोषी साबित हो सके। इसका यह भी मतलब होता है कि साधवी और अन्य दूसरे पांच आरोपियों को बिना किसी ठोस सबूत के ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी जिस अपराध ने उनकी जिंदगी के आठ कीमती साल छीन लिए, उस अपराध को उन्होंने किया ही नहीं था। ऐसे ही हालात दूसरे पक्ष के भी हैं। कई आतंकी मामले में इस्लाम को मानने वाले नौजवान, 20-20 साल नाहक जेल काटे और बाद में तथ्यों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया।

थोड़ा साध्वी प्रज्ञा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल, साध्वी मध्य प्रदेश के भिंड की रहने वाली हैं लेकिन उनका परिवार पहले राजस्थान के सेखावटी से आकर झांसी में बसा और बाद में उनका परिवार झांसी से भिंड में जाकर बस गया। साध्वी तीन बहन और एक भाई हैं। उनके पिता डॉक्टर चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे इसलिए साध्वी भी पहले आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से जुड़ी। इसके बाद वह विश्व हिन्दू परिषद् से जुड़ गयी। कहा जाता है कि जूना अखारे के संत अवधेशानंद गिरी से उन्होंने इलाहाबाद कुंभ में सन्यास की दीक्षा दी। इतिहास में परास्नातक प्रज्ञा हमेशा से ही दक्षिणपंथी संगठनों के संपर्क में रहीं।

वे कई बार अपने भड़काऊ भाषणों के लिए सुर्खियों में रहीं। 2002 में उन्होंने संघ परिवार के संगठनों से अपना नाता तोड़ लिया और जय वन्दे मातरम जन कल्याण समिति का गठन किया। इसके बाद उन्होंने एक राष्ट्रीय जागरण मंच का भी गठन किया। इस दौरान वह मध्य प्रदेश और गुजरात के एक शहर से दूसरे शहर जाती रहीं। इस बीच उनके पिता चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह अपने परिवार सहित गुजरात के सूरत में आकर रहने लगे। वहां चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने लगे और छोटी बेटी एवं दामाद के साथ किराए के मकान में रहने लगे। आपको यह भी बता दें कि मालेगांव साध्वी को सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी सूरत से ही हुई थी। दरअसल, 2008 में मालेगांव में बम विस्फोट हुआ उसमें महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए उनके ही पसलेचा नामक शिष्य के घर पर बुलाया और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। याद रहे जिस समय साध्वी गुजरात के सूरत से गिरफ्तार की गयीं थी उस समय वहां नरेन्द्र मोदी की सरकार थी और भाजपा के किसी नेता ने वहां उनका साथ नहीं दिया। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्थानीय कार्यकर्त्ता और विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने साध्वी को सहयोग जरूर किया लेकिन समय के साथ ही साथ वे लोग भी साध्वी का साथ छोड़ते चले गए। गुजरात पुलिस के द्वारा भी साध्वी के बहनोई भगवान झा को प्रताड़ित किया गया। आज वही साध्वी एक बार फिर से राजनीति की बिसात पर हैं।

खैर 2017 में एनआईए के एक विशेष कोर्ट ने इनपर लगी मकोका की धाराएं हटा दी, एवं गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आंतकवाद पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। आपको यह भी बता दें कि जब साध्वी और उनके साथ कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किए गए थे तो देशभर के पुलिस प्रमुखों की बैठक को संबोधित करते हुए तत्कालीन गृहसचिव राजकुमार सिंह ने दक्षिणपंथी आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया और

उस शब्द को कॉरपोरेट समर्थक मीडिया व भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए भगवा आतंकवाद की संज्ञा दे दी और उसे देशभर में प्रचारित किया गया। संयोग से आज राजकुमार सिंह भाजपा के सांसद हैं और वे मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। राजकुमार सिंह एक बार फिर से बिहार के आरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन संयोग देखिए भगवा आतंकवाद उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, जबकि इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के बनते ही न केवल एनआईए के वकील बदल दिए गए अपितु एक ईमानदार और होनहार पुलिस अधिकारी, जिसने एमआईए को एक तरह से खड़ा किया, संजीव कुमार सिंह को पद से हटा कर वापस भोपाल भेज दिया गया। खैर स्थितियां बदल चुकी है। साध्वी प्रज्ञा ने 17 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी ने उन्हें सत्रहवीं लोकसभा के सदस्य के लिए भोपाल से लोकसभा का टिकट दे दिया। कांग्रेस ने यहां मध्य प्रदेश में लम्बे समय तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है।

दरअसल, कांग्रेस के शासन में एनआईए का गठन हुआ। हालांकि इस प्रकार की जांच एजेंसी बनाने की सहमति सैद्धांतिक रूप से वाजपेयी जी के शासनकाल में ही हो गयी थी लेकिन इसका गठन मनमोहन सरकार ने की। एनआईए देश की एक मात्र ऐसी जांच एजेंसी है जिसके पास संसद की ताकत है। संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से इस जांच एजेंसी का गठन किया गया है। मुंबई आतंकी हमले के बाद 31 दिसंबर 2008 को इसका गठन किया गया। पूर्व एनआईए ऑप्रेशन आईजी संजीव सिंह बताते हैं कि जब वे यहां आए थे तो उनके पास मात्र 6 अधिकारी थे और संसाधनों का भी अभाव था। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती देशभर में एक नेटवर्क खड़ा करने का था। अब एनआईए बेहद मजबूत जांच एजेंसी मानी जाती है लेकिन इस घटना के बाद इस जांच एजेंसी पर भी प्रश्न खड़े होने लगे हैं। प्रश्न दोनों ओर से खड़े हो रहे हैं। प्रश्न हिन्दूवादी भी खड़े कर रहे हैं और प्रश्न मुस्लिम चिंतक भी कर रहे हैं लेकिन इस मामले में संजीव जी का कहना है कि हम और हमारी एजेंसी हर समय ईमानदारी से तथ्यों की व्याख्या की है। 2008 के मालेगांव बमकांड की जांच का कार्य एक अप्रैल 2011 को एनआईए को सौंपा गया था। उससे पहले जांच का जिम्मा महाराष्ट्र एटीएस के पास था। एटीएस ने दो आरोप पत्र (मुख्य और पूरक) दायर भी कर चुकी थी। यानी एनआईए को केस दिए जाने तक करीब ढाई साल प्रज्ञा (गिरफ्तारी-23 अक्टूबर 2008) एटीएस की कस्टडी या न्यायिक हिरासत में रहीं। महाराष्ट्र एटीएस पर साध्वी प्रज्ञा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि कस्टडी के दौरान उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया और एक महिला के रूप में उनकी मर्यादा को तार-तार किया गया। ले-देकर सबूत के रूप में एटीएस के पास क्षतिग्रस्त बाईक और सभी आरोपियों एवं गवाहों के इकबालिया बयान थे। यानी बिना पुख्ता सबूत के जांच एजेंसियों ने प्रज्ञा को लंबे समय तक अपनी हिरासत में रखा।

इधर, पूरक आरोपपत्र में एनआईए ने एटीएस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरोप इतने ज्यादा संगीन हैं कि एटीएस की भूमिका की ही जांच की जरूरत महसूस होने लगी है। यहां फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी कर्नाटक के डायरेक्टर रह चुके बीएम मोहन के दावे पर गौर करना होगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में कई अहम नार्को टेस्ट हुए थे। बीएम मोहन ने कुछ साल पहले मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया था कि सिमी के कुछ आतंकियों का नार्को टेस्ट करते समय समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट के बारे में अहम जानकारियां मिली थी। मोहन का दावा था कि इन इनपुट्स के आधार पर जांच एजेंसियां अगर सबूत जुटातीं, तो आतंकवादी धमाकों की कहानी कुछ और होती। उनका कहना है कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाइडिटेक्टर तीनों ही टेस्ट में सिमी के आतंकियों ने समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट में हाथ होने की बात स्वीकारी थी। इन लोगों ने सिमी चीफ सफदर नागौरी की पूरी साजिश का खाका तैयार किए जाने की बात भी कही थी। समझौता ब्लास्ट मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट पंचकूला में स्वामी असीमानंद के अधिवक्ता नरदेव शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण में जो जांच भारती अरोड़ा ने की थी उसमें कहीं भी आतंकवाद के कथित हिन्दू मॉडयूल की चर्चा नहीं है। अमेरिकी जांच एजेंसी ने भी इसकी चर्चा नहीं की साथ ही प्रथम चरण के केन्द्रीय जांच में भी इसकी चर्चा नहीं है लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी है हिन्दू संत और हिन्दूपंथी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को फंसा दिया गया। इस मामले में एनआईए की जांच प्रक्रिया पर भी नरदेव शर्मा ने सवाल खड़े किए थे। अपने क्लाइंट की ओर से न्यायालय में दाखिल आवेदन में उन्होंने लिखा है कि एनआईए न तो ब्लास्ट के आरोपी कलसांग्रा को पकड़ पायी और न ही संदीप डांगे पकड़े गए हैं। सुनिल जोशी की हत्या हो चुकी है। एनआईए या फिर एटीएस के पास सबूत के तौर पर प्रज्ञा के मोटरसाईकल के अलावा और कुछ भी नहीं है जबकि असीमानंद पर आतंकियों को 25 हजार रुपये किसी दूसरे के माध्यम से पहुंचाने का आरोप है। नरदेव शर्मा के अनुसार ऐसे कमजोर तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के केस में जांच एजेंसियां कैसे व्यापक संज्ञान ले सकती है?

कुल मिलाकर आतंकवाद का यह मॉडयूल बेहद पेचीदा हो चुका है। इसमें तथ्य क्या है इसकी जानकारी खुद जांच एजेंसियों के पास भी नहीं दिख रही है। जांच एजेंसियां या तो कन्फ्यूज है या वह राजनीतिक दबाव के कारण लोगों को कन्फ्यूज करने की कोशिश की है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि जब प्रज्ञा विपरीत परिस्थिति में थी तो अपनों ने उनका साथ क्यों छोड़ा? दूसरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी कथित रूप से षडयंत्र कर रही थी तो मध्य प्रदेश और गुजरात की भजपा सरकार उस समय क्या कर रही थी? उस समय दोनों प्रदेशों से कथित हिन्दू आतंकवादी पकड़े जा रहे थे और यह दोनों सरकारें मौन धारण किए हुए थी, जबकि गुजरात के मोडासा ब्लास्ट में तो गुजरात पुलिस और एनआईए की जांच और व्याख्या में कोई फर्क नहीं है। इस मामले में गांधीनगर के तत्कालीन आईजी अरुण कुमार शर्मा का कहना है कि केन्द्रीय जांच एजेंसी केवल तथ्यों की व्याख्या करती है, जांच तो स्थानीय पुलिस ही करती है। तीसरा सवाल यह है कि जिस प्रशासनिक अधिकारी ने सबसे पहले दक्षिणपंथी आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया और उस शब्द के आधार पर ही भगवा आतंकवाद शब्द का श्रृजन हुआ वे आज भाजपा में हैं और मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। ऐसे कई प्रश्न उलझे हुए हैं। प्रज्ञा का उत्थान, पतन और फिर उत्थान बेहद महत्वपूर्ण है। कई पड़ाव

# कोई भी मतदाता ना छूटे प्रदेश निर्वाचन आयोग ने कसी कमर

**शिमला/शैल।** हिमाचल के मुख्य निवार्चन अधिकारी देवेश कुमार ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी की प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के लिये कुल 55 उम्मीदवारों ने नामाकन भरा था जिसमें 9 नामांकन रद्द हुये और 1 नामांकन वापिस हुआ अब कुल 45 उम्मीदवार जिनमें शिमला से 6, हमीरपुर से 11 मण्डी से सबसे अधिक 17 और कांगड़ा से 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं । 2019 लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कुल 5330154 मतदाता हैं जिसमें 2724111 पुरूष 2605996 महिला तथा 47 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। प्रदेश के 152390 नये मतदाता पहली बार अपना मतदान करेंगे और 1334823 मतदाता प्रदेश में 30 वर्ष से कम आयु के है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे।

चुनाव आयोग द्वारा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिये प्रदेश भर में कुल 207 फ्लाइंग स्क्वाड, 207 स्टेटिक सर्विलांस टीम, 77 सहायक व्यय पर्यवेक्षक, 134 वीडियो निगरानी दल, 70 वीडियो देखने वाली टीमें, 72 लेखा दलों का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 सामान्य पर्यवेक्षक 5 व्यय पर्यवेक्षक तथा पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये है। केन्द्रिय सुरक्षा बलों की 47 टुकिडयां केन्द्रिय गृह मन्त्रालय द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश के कुल 7723 मतदान केन्द्रो में से कुल 373 अति संवेदनशील तथा 946 संवेदनशील चिन्हित किये गये है। प्रदेश में कुल 7730 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें से 7723 सामान्य तथा 7 सहायक मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदान केन्द्रो में EVM/VVPAT द्वारा मतदान करवाया जायेगा। EVM/VVPAT सभी जिलों को भेज दी गई है तथा इसके अतिरिक्त 25% रिजर्व EVM/VVPAT भी सबंधित जिला मुख्यलायों तक पंहुचा दी गई है।

मतदान के संचालन हेतु 7730 पीठासीन अधिकारी तथा 23,190 मतदान अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन अधिकारियों को 3 चरणों में पूर्वाभ्यास करवाया जायेगा। पहला पूर्वाभ्यास 11 से 17 अप्रैल के मध्य करवा दिया गया है दूसरा पूर्वाभ्यास 6 तथा 7 मई को करवाया

जायेगा। तीसरा तथा अन्तिम पूर्वाभ्यास 16 तथा 17 मई को करवाया जायेगा तथा इन्ही दो दिनों में मतदान दल अपने मतदान केन्द्रों के लिये प्रस्थान करेंगे। मतदाना सूचियां संबधित जिला मुख्यालयों तक पहुंचा दी गई हैं। मतदाताओं की सुविधा को लेकर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निश्चित मूलभूत सुविधायें जैसे की रैम्पस पीने हेतु स्वच्छ जल, शौचालय, बिजली, पहचान सूचक प्रतीक्षालय छायादार कक्ष, फर्नीचर, हेल्प डैक्स, 2 स्वयंसवेक इत्यादि सुविधायें प्रदान की जायेगी।

प्रदेश के इस लोकसभा चुनाव में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाला मतदान केन्द्र बड़ा भंगाल में रह रहे बुजुर्ग मतदाताओं के लिये बड़ा भंगाल में ही एक सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है। प्रदेश में लाहौल स्पीति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत टाशीगांग मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है। जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 15,256 फिट हैं ये मतदान केन्द्र विश्व भर में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केन्द्र हैं तथा इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 49 है।

इस समय प्रदेश में कुल 999 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इस बार प्रदेश के 136 मतदान केन्द्र केवल महिला मतदान कर्मियों द्वारा तथा 10 मतदान केन्द्र दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेगे। जिला मण्डी में ही दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा 2 मतदान केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

प्रदेश में इस बार 3 जिले मण्डी, हमीरपुर तथा लाहौल स्पीति जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष मतदाताओं से अधिक हैं। वद्ध एंव अस्वस्थ्य मतदाताओं को प्रदेश में कुल 7 सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

प्रदेश में सभी मतदाताओं को उनके घर द्वार पर फोटो वोटर स्लीप विपरित की जायेगी। इस वोटर स्लीप में मतदाता से संबधित मतदान करने हेतु विभिन्न जानकारियां उपलब्ध होंगी। प्रदेश भर में 12,25,147 घर द्वारों पर वोटर गाइड उपलब्ध करवाई जायेगी जिसमें मतदान प्रक्रिया से संबधित समस्त जानकारियां उपलब्ध होगी। मतदान दिवस से एक दिन पहले प्रदेश के समस्त मतदाताओं को एसएमएस के माध्यम से मतदान करने का आहवान किया जायेगा। मतदाता दिवस पर भी प्रदेश के समस्त मतदाताओं को एसएमएस के माध्यम से रिमाईडर भेजा जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग का इस चुनाव में आर्दश वाक्य हैं कोई भी मतदाता ना छूटे। उक्त वाक्य को चरितार्थ करने के लिये विभाग द्वारा दिव्यांग, महिला, बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान केन्द्र तथा वापिस घर पंहुचाने के लिये वाहन का प्रबंध किया जायेगा। अस्थि दोष दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर वहील चेयर उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त मतदाता पीडब्लयूडी ऐप द्वारा भी वहील चेयर बुक करवा पायेगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 2 स्वंयसेवी उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक अस्थाई शिशुसदन स्थापित किया जायेगा जहां मतदान करने आई महिलाओं के शिशुओं की अल्पकालीन देखभाल स्वयंसेवीयों द्वारा की जायेगी। वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र में कतार रहित प्रवेश की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

चुनाव आयोग के पास अभी तक कुल 336 शिकायतें आई है जिन पर कारवाई की जा रही है। अभी तक प्रदेश में 9,74,835 लीटर शराब पकड़ी जा चुकी हैं जिसकी कीमत आठ करोड़ 51 लाख आंकी गई है। 21,88,565 रूपये कैश बरामद किया चुका है। एक करोड़ की कीमत की चरस, गांजा, दवाईयां, अफीम जब्त की जा चुकी है। अभी तक कुल दस करोड़ दो लाख की धड़पकड़ की जा चुकी है।

# एच.पी.फॉरेस्ट वूमेन वेलफेयर सोसाइटी की नयी कार्यकारिणी गठित

**शिमला/शैल।** एच.पी.फॉरेस्ट वूमेन वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव शिमला में समपन हुआ जिसमें पूनम श्रीवास्तव और शबनम नेगी को सोसाइटी के संरक्षक और सह-संरक्षक डॉ. सविता और रेणु सुयाल को सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रेणु कटैक और नीलम गुप्ता संयुक्त रूप से सोसाइटी के संयुक्त सचिव जब कि मीनाक्षी सूद को सोसाइटी का कोशाध्यक्ष नियुक्त किया गया

एच.पी.फॉरेस्ट वूमेन वेलफेयर सोसाइटी का गठन 2010 में किया गया था। सोसाइटी लाभार्थियों की कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होती है और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों की मद्द में हमेशा आगे रही है। सोसाइटी की अध्यक्ष डॉ. सविता ने कहा कि वन विभाग के कर्मियों के परिवारों के लिए सोसाइटी अपनी कल्याणकारी गतिविधियों को ज़ारी रखेगी। सोसाइटी सफाई एवं व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़े विभिन्न समसामायिक मुद्दों पर अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित करके महिलाओं और परिवार कल्याण के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी रक्तदान शिविर, शिक्षा कार्यक्रम और अन्य कार्यशालाएं भी आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी लाभार्थियों को स्वरोज़गार प्रदान करने की सम्भावनाओं को भी तलाशेगी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पहले कदम के तौर पर सोसाइटी 8 मई, 2019 को रेड-क्रॉस दिवस के अवसर पर रेड-क्रॉस सोसाइटी के लिए धन जुटाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से सोसाइटी वन विभाग को वर्तमान सामाजिक मुद्दों को सम्बोधित करने में सहायता करेगी।

# मलेशिया के उच्चायुक्त को ग्लोबल इंवेस्टर मीट का न्योता

**शिमला/शैल।** मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने अपनी दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान मलेशिया के उच्च आयुक्त डॉ. डाटो' हिदायत अब्दुल हमीद के साथ बैठक की तथा उन्हें धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर मीट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्य सचिव ने मलेशिया के दूतावास से मलेशिया की प्रमुख कम्पनियों से हिमाचल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मलेशिया के साथ निवेश सांझेदारी के लिए हाइड्रो-इलैक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, बागवानी, खाद्य प्रसंस्कार, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल व वेलनेस सैंटर, शहरी विकास व आवास, आईटी व इलैक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकलस आदि क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा मलेशिया में एक रोड शो करने पर भी विचार किया जा रहा है।

मलेशिया के उच्चायुक्त ने इन्वेस्टर मीट में आमंत्रण के लिए मुख्य सचिव का आभार व्यक्त किया और सीआईआई और चैम्बर आम्फ बिजनेस के सहयोग से रोड शो करने के लिए विचार का स्वागत किया। मलेशिया की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखती है तथा साहसिक खेलों में उनकी विशेष रूचि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बौद्ध पर्यटक सर्किट तथा साहसिक पर्यटन मलेशिया और हिमाचल प्रदेश के लोगों की एक जैसी रूचियां हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव के साथ प्रधान आवासीय आयुक्त संजय कुंडू, सीआईआई के निदेशक अमिताभ श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

# उपायुक्त ने तोद घाटी के लोग किये जागरूक

**शिमला/शैल।** 19 मई को प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति, अश्वनी चौधरी ने लाहौल-स्पीति की तोद वैली के लोगों

को मतदान के लिए जागरूक किया।

मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम ''स्वीप'' के तहत उपायुक्त ने ग्राम पंचायत कोलंग और युरनाथ के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से अपील कि सभी स्वयं भी मतदान करें और अपने आस-पड़ोस, रिस्तेदारों और 18 साल के नये मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि जिला के लोगों में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग मतदान करने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला की सभी 41 पंचायतों में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

उपायुक्त ने इस अवसर पर दारचा सुम्दो, जिस्पा, गैमूर, कोलंग और युरनाथ पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी किया और यहां उपलब्ध करवाई जा रही सभी बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 92 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं और सभी मतदान केंद्रों पर भारत चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित सभी बुनियादी सुविधाओं को पुरा कर दिया गया है। इस अवसर पर स्वीप के नोडल अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे।

# जनरल ड्यूटी के लिए पहली बार आर्मी में होगी महिला भर्ती

**शिमला/शैल।** भारतीय थल सेना में जनरल ड्यूटी के लिए पहली बार महिलाओं की भर्ती होगी। यह जानकारी देते हुए भर्ती निदेशक, भर्ती कार्यालय मण्डी कर्नल सोमराज गुलिया ने बताया कि भर्ती के लिए इच्छुक युवतियों को भारतीय थल सेना की अधिकारिक वेबसाइट (www.joinindianarmy.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि 100 पदों को भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून, 2019 है। आयु सीमा साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यार्थी की शिक्षा दसवीं पास और इसके समकक्ष योग्यता होनी अनिवार्य है इसके अतिरिक्त हर विषय में 33 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य किया गया है।

कर्नल गुलिया ने बताया कि आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद ईमेल के द्वारा योग्य अभ्यार्थियों को भर्ती के लिए 20 से 27 सितंतबर, 2019 को खरगा स्टेडियम अंबाला में बुलाया जाएगा। आवेदकों को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके लिए कद 142 सेंटीमीटर होना चाहिए व 1600 मीटर की दौड़ साढ़े सात मिनट में पूरी करनी होगी। पूर्व सैन्य कर्मियों और शहीदों के आश्रित परिवारों की युवतियों को मापदंडों में विशेष छूट दी जाएगी।

भर्ती के लिए भर्ती कार्यालय मण्डी द्वारा विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में युवतियों को इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

# सांसद निधि के आयने में हमारे सांसद

**शिमला/शैल।** कानून के निर्माता और विकास के प्रतीक होते हैं हमारे सांसद यह आम की धारणा है। इस धारणा पर कौन कितना खरा उतरता है इसका आंकलन करने के लिये कोई कसौटी नही बन पायी है। जहां इन लोगों को कानून के निर्माताओं की संज्ञा दी जाती है वहीं पर एक कड़वा सत्य यह भी है कि विधानसभाओं से लेकर संसद तक गंभीर आपराधिक छवि तक के लोग जनता द्वारा चयनित होकर संसद में माननीय हो जाते हैं। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार इन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाकर माननीय बनने का अवसर प्रदान करना है। जब यह जनता की अदालत से चयनित होकर माननीय हो जाते हैं तब कानून की अदालत का रूख भी इनके प्रति बदल जाता है क्योंकि बहुत अरसे से देश की शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दे रखे हैं कि अधीनस्थ अदालत एक वर्ष के भीतर इनके मामलों के फैसले करे। इसके लिये दैनिक आधार पर इनके मामलों की सुनवायी की जाये। यह निर्देश करने पर अदालत को सराहना तो मिल गयी लेकिन इन निर्देशों पर अमल कितना हुआ है यह जानने का प्रयास शायद आज तक नही हो पाया है।

इस परिदृश्य में फिर यह सवाल उभरता है कि आम मतदाता इनका व्यक्तिगत और व्यवहारिक आकलन कैसे करे। क्योंकि केन्द्र से लेकर राज्य तक चुनावों में हर राजनीतिक दल अपना – अपना चुनाव घोषणापत्र जारी करता है। सरकार बनने के बाद इस घोषणापत्र को नीति पत्र बना दिया जाता है और इसके अनुसार सरकार काम करने लग जाती है। इस तरह फिर सांसद/विधायक की अपनी परफार्मेन्स का आकलन नही हो पाता है। शायद इसी स्थिति को ध्यान में रखकर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से अलग हटकर सांसद/विधायक विकास नीतियों का प्रावधान किया गया है। क्योंकि इस निधि से सांसद/ विधायक अपनी ईच्छानुसार खर्च करता है। इस खर्च के लिये दिशा-निर्देश तय किये गये हैं लेकिन इन निर्देशों में यह नही है कि इस निधि में से खर्च करने के लिये किसी अन्य से कोई अनुमति लेनी होगी। इस नाते यह सांसद निधि स्वत: ही एक ऐसा मानक बन जाता है जिसके खर्च करने पर नजर रखने से यह पता चल जाता है कि इसमें ''सबका साथ सबका विकास'' के सिन्द्धात पर काम किया गया है या नही। किसके साथ पक्षपात हुआ है या सही में यह खर्च विकास पर हुआ है या नही। इस सबकी जानकारी इससे मिल जाती है।

इस मानक पर प्रदेश के सांसदो का आंकलन करना बहुत आसान हो जाता है। प्रदेश में लोकसभा की चार सीटे हैं और विधानसभा के लिये विधायकों की 68 सीटें हैं। इस तरह प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सत्रह-सत्रह विधानसभा क्षेत्र आते हैं प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष पांच करोड़ की सांसद विकास निधि मिलती है। इस समय वर्तमान में प्रदेश में कांगड़ा से शान्ता कुमार, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर मण्डी से रामस्वरूप शर्मा और शिमला से वीरेन्द्र कश्यप सांसद हैं। इनमें से अनुराग ठाकुर और रामस्वरूप को भाजपा ने पुन: प्रत्याशी बनाया है। शान्ता और वीरेन्द्र कश्यप को इस बार बदल दिया गया है। वीरेन्द्र कश्यप दो बार लगातार सांसद रहे हैं। इस नाते उन्हें पचास करोड़ सांसद निधि के रूप में मिले हैं। अनुराग 2008 में उपचुनाव जीत कर सांसद बन गये थे और तब से लगातार सांसद हैं उन्हें 55 करोड़ की सांसद निधि मिली है जबकि शान्ता कुमार और रामस्वरूप को 25-25 करोड इस निधि में मिले हैं। एक सांसद के पास सत्रह विधानसभा क्षेत्र हैं इस नाते उसे 25 करोड़ का आवंटन इन सत्रह हल्कों पर एक समान करना है। इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिस्से में 1,47,05,889 रूपये आते हैं। इस गणित से यह सामने आ जायेगा कि हमारे सांसदो ने विधानसभा क्षेत्रवार क्या इसी अनुपात में अपनी सांसद निधि का आंवटन किया है की नहीं। इसके लिये सांसदो की इस निधि के खर्च का ब्यौरा लेने के लिये आरटीआई का सहारा लिया गया था।

Year wise Detailed Report of All Sanctioned Schemes For Financial Year = 2014-15 to 2018-19 for Scheme Head = MPS and Sanction Date is between 01/04/2014 and 17/04/2019

Scheme Name | Executing Agency | Constituency | Scheme Head | Sub Head | Block Name | Panchayat | Status | Amount

## अनुराग से बिलासपुर को 11 वर्षो में मिले 11,46,96,351

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अनुराग ठाकुर 2008 से कर रहे हैं इसलिये उन्हें ग्याहर वर्षो में 55 करोड़ की सांसद निधि मिली है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बिलासपुर के चार, हमीरपुर-ऊना के पांच-पांच कांगड़ा के दो और मण्डी का एक विधानसभा क्षेत्र आता है। अनुराग से पहले यहां से सुरेश चन्देल भाजपा से सांसद रह चुके हैं जो अब कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। बिलासपुर से ही राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा मोदी सरकार में स्वास्थ्य मन्त्री हैं। अनुराग के खिलाफ बिलासपुर के साथ भेदभाव बरतने का भी आरोप लगता है। सांसद निधि के आवंटन पर यदि नजर डाले तो अनुराग को पूरे कार्यकाल मे बिलासपुर को 11,46,96,351 मिले हैं बिलासपुर के चार विधानसभा क्षेत्रो के हिसाब से यहां पर कराब 12 करोड़ मिलने चाहिये थे लेकिन ऐसा हुआ नही है। इस तरह सांसद निधि के आवंटन के आंकड़े भी बिलासपुर के साथ भेदभाव के आरोपों को पुरख्ता करते हैं।

| | Total Schemes | Sanctioned Amount |
|---|---|---|
| 2008-09 | 68 | 86,56,250 |
| 2009-10 | 51 | 63,92,000 |
| 2010-11 | 43 | 43,25,000 |
| 2011-12 | 91 | 98,78,240 |
| 2012-13 | 91 | 1,22,13,968 |
| 2013-14 | 138 | 1,46,58,000 |
| 2014-15 | 101 | 1,28,33,805 |
| 2015-16 | 83 | 94,00,000 |
| 2016-17 | 56 | 53,35,000 |
| 2017-18 | 123 | 1,20,01,305 |
| 2018-19 | 193 | 1,90,02,783 |
| | 1038 | 11,46,96,351 |

## शान्ता कुमार ने कांगड़ा को दिये 26 करोड़

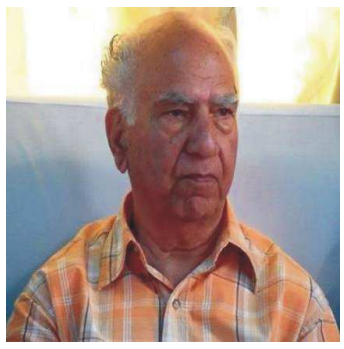

कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में जिला कांगड़ा की तेरह और चम्बा के चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उन्हे 25 करोड़ की सांसद निधि मिली है। जिसमे से अकेले कांगड़ा में ही उन्होंने 26 करोड़ का आवंटन कर दिया है। इस खर्च का विवरण हर जिला के जिलाधीश से आता है। ऐसे में जब शान्ता कुमार ने कांगड़ा के ही 13 विधानसभा क्षेत्रों में यह आंवटन कर दिया है तो स्वभाविक है कि चम्बा के हिस्से में कुछ नही आया है। शान्ता का यह आंवटन 2112 कार्य योजनाओं पर हुआ है लेकिन इनमे से केवल 1033 कार्य ही पूरे हो पाये हैं। इस तरह शान्ता कुमार भी सांसद निधि के एक समान वितरण के मानक पर खरे नही उतरते हैं। इसलिये यह आशंका हो गयी है कि शान्ता कुमार द्वारा की गयी चम्बा उपेक्षा चुनावी गणित न बिगाड दे क्योंकि कांगड़ा में फिर हर विधानसभा क्षेत्र के साथ एक बराबर आंवटन नही हुआ है।

| | Total Schemes | Sanctioned Amount |
|---|---|---|
| 2014-15 | 388 | 5,38,57,564,00 |
| 2015-16 | 549 | 5,94,04,782,00 |
| 2016-17 | 450 | 5,12,45,027,00 |
| 2017-18 | 437 | 5,58,94,051,00 |
| 2018-19 | 293 | 4,79,06,095,00 |
| | 2112 | 26,81,07,519,00 |

## मण्डी के रामस्वरूप भी नहीं कर पाये हैं एक समान आवंटन



मण्डी संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद रामस्वरूप शर्मा को भाजपा ने फिर चुनाव में उतारा है। मण्डी के जिन पंडित सुखराम के कन्धों का सहारा लेकर भाजपा ने पहली बार सरकार का कार्यकाल पूरा करने का श्रेय लिया था। वह पंडित जी अब भाजपा छोड़ कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। मण्डी संसदीय क्षेत्र में मण्डी के नौ, कुल्लु के चार, लाहौल-स्पिति, किन्नौर, भरमौर और रामपुर के विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रामस्वरूप शर्मा को 25 करोड़ की सांसद निधि मिली है। इसमें से कुल्लु चार विधानसभा क्षेत्रों का हिस्सा करीब 5,88,23,532 रू. बनता है लेकिन आरटीआई की सूचना के अनुसार कुल्लु को करीब 3 करोड़ ही मिले हैं रामपुर, किन्नौर, भरमौर और लाहौल स्पिति में यह आवंटन अनुपातन और भी कम है। ऐसे में यह बड़ा सवाल बन गया है कि इन लगभग नजरअन्दाज हुए विधानसभा क्षेत्रों से रामस्वरूप को पुन: समर्थन कैसे और कितना मिल पायेगा।

| Schemes | Sanctioned Amount |
|---|---|
| 7 | 0,36,000-00 |
| 23 | 0,51,000-00 |
| 23 | 0,44,000-00 |
| 23 | 0,57,000-00 |
| 23 | 0,37,50,000 |
| 126 | 2,98,00,00-00 |

## वीरेन्द्र कश्यप ने भी सांसद निधि के आवंटन में पक्षपात किया है

वीरेन्द्र कश्यप पिछले दस वर्षो से शिमला से सांसद हैं। भले ही भाजपा ने उन्हे कैश ऑन कैमरा के आरोपों के साये में इस बार प्रत्याशी नही बनाया है। लेकिन उनके दस वर्षो के कार्यकाल की कारगुजारी का असर पार्टी के इस बार के उम्मीदवार की सफलता की संभावनाओं पर पड़ेगा ही यह तय है। भाजना ने इस बार सिरमौर से वर्तमान विधायक सुरेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। सिरमौर का हाटी समुदाय लम्बे अरसे से उन्हें जनजातीय दर्जा देने की मांग कर रहा है। वीरेन्द्र कश्यप अपने दस वर्ष के कार्यकाल में मोदी की सरकार होने के बावजूद यह मांग पूरी नही करवा पाये हैं। जबकि मोदी स्वयं हिमाचल से भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं और इस नाते इस मांग से परिचित भी रहे हैं। अब कश्यप ने सिरमौर के पांच विधानसभा क्षेत्रों को केवल 6,88,55000 की सांसद निधि आंवटित की है जब कि यह रा ाी 15 करोड़ के करीब बनती है। कश्यप को दस वर्षो के कार्यकाल में पचास करोड़ की निधि मिली है। इस निधि का आंवटन अब सवालों के घेरे में आता जा रहा है।

| | Total Schemes | Sanctioned Amount |
|---|---|---|
| 2014-15 | 105 | 1,40,95,000 |
| 2015-16 | 72 | 94,70,000 |
| 2016-17 | 89 | 1,69,10,00 |
| 2017-18 | 56 | 1,14,50,000 |
| 2018-19 | 84 | 1,74,30,000 |
| | 406 | 6,88,55000 |

सांसद निधि के आंकड़ो से यह स्पष्ट है कि हमारे सांसद सारी निधि का उपयोग नही कर पाये हैं। इस निधि के तहत जो कार्य किये गये हैं उसमें से करीब 30% कार्य ही अब तक पूरे हो पाये हैं। शेष कार्य कब पूरे होंगे इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। क्योंकि इन सांसदो ने जो गांव आदर्श गावं बनाने के लिये गोद लिये थे उनकी दशा में भी विशेष सुधार देखने में नही आया है और इसके लिये धन का अभाव ही कारण रहा है। जबकि इन आदर्श गांव के लिये सांसद निधि से अलग धन का प्रावधान करने का दावा किया गया था जो कि पूरा हो नही पाया है। इस तरह सांसद निधि के आवंटन और आदर्श गांव के मानकों पर हमारे सांसदो का रिपोर्ट कार्ड ऐसा नही है जिससे सरकार और पार्टी को कोई बड़ा चुनावी लाभ मिलने की संभावना बनती हो।